● वर्ष : 17 ● अंक : 183 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS
RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928
www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित गुरुवार 23 अप्रैल 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

राजनाथ सिंह ने जर्मन उद्योग को 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत मिलकर काम करने का न्योता दिया

- भारत और जर्मनी के बीच लंबे समय तक चलने वाले सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों पर जोर
- जर्मनी में रक्षा मंत्री राजनाथ ने दिया पाकिस्तान को सख्त संदेश, सभी पड़ोसी ठीक, बस एक ही परेशानी

एजेंसी। नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मन उद्योग को उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत मिलकर काम करने का न्योता दिया। रक्षा मंत्री ने बर्लिन में हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के परिसर में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित की और भारत और जर्मनी के बीच लंबे समय तक चलने वाले सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों पर जोर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए भारत की रणनीति वैश्विक संकटों का जवाब देने की उसकी क्षमता को दिखाती है। रक्षा मंत्री ने बर्लिन में जर्मन सांसदों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक खरीद प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह मिलकर विकास करने का न्योता है। उन्होंने भारत और जर्मनी के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के बीच बेहतर सहयोग की जोरदार वकालत की। यूरोपियन देश के अपने तीन दिन के दौरे के पहले दिन रक्षा और सुरक्षा पर जर्मन संसद की स्टैंडिंग कमेटी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज दुनिया नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है। तकनीक में बदलाव ने स्थिति को बहुत मुश्किल और आपस में जुड़ा हुआ बना दिया है। उन्होंने कहा कि बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की इच्छा के साथ एक नया तरीका खोजना आज की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम जर्मनी के उद्योगों की पहले से बनी ताकत को पहचानते हैं। साथ ही भारत में भी हमारे स्टार्ट-अप और आगे बढ़ने वाली प्राइवेट कंपनियां तेजी से हमारी बड़ी और पहले से बनी डिफेंस कंपनियों की काबिलियत को बढ़ा रही हैं और उन्हें पूरा कर रही हैं। यह एक ऐसा एरिया है, जहां भारत और जर्मनी एक-दूसरे के पूरक हैं और हमारी साझेदारी और मजबूत हो सकती है। आज के जमाने की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए राजनाथ सिंह ने मिलकर जवाब देने और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम यूरोपियन यूनियन पर भी विचारों में साफ समानता देख रहे हैं, जो भारत के साथ जुड़ने की बढ़ती रफ्तार में दिखती है, जिसमें इंडिया-ईयू डिफेंस और रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। रक्षा मंत्री ने दोहराया कि भारत और जर्मनी न सिर्फ रणनीतिक साझेदार हैं, बल्कि आज के समय में वैश्विक बातचीत को आकार देने में अहम आवाज भी हैं। जब इस युग के इतिहास को लिखा जाएगा, तो भारत-जर्मनी साझेदारी कूटनीति की एक मिसाल के तौर पर खड़ी होगी, जो संकट के जवाब में नहीं, बल्कि दो परिपक्व लोकतंत्रों के इस रास्ते पर एक साथ चलने के पक्के इरादे से बनी होगी।

होर्मुज संकट से भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता सीधा असर

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि होर्मुज में पैदा हो रही बाधाएं केवल दूर की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा असर भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जर्मनी के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिंह ने वहां की संसद की रक्षा और सुरक्षा समिति को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया आज नए तरह के सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है। तेजी से बदलते तकनीक ने हालात को और जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में देशों को नई सोच के साथ आगे बढ़ने और बदलते माहौल के मुताबिक खुद को ढालने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री ने भारत और जर्मनी के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने की भी वकालत की। उनका यह दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम एशिया में पिछले 50 दिनों से जारी तनाव का असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह सिर्फ अंतरराष्ट्रीय

देशों को नई सोच के साथ आगे बढ़ने और बदलते माहौल में खुद को ढालने की जरूरत

मुद्दा नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता से जुड़ा सीधा खतरा है। उन्होंने बताया कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में किसी तरह का व्यवधान होता है, तो उसका असर तुरंत दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ही सक्रिय और समन्वित रणनीति अपनाई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह केवल खरीद तक सीमित पहल नहीं है। यह दुनिया के देशों के लिए एक खुला निमंत्रण है कि वे भारत के साथ मिलकर तकनीक विकसित करें, नवाचार करें और नए समाधान तैयार करें। उन्होंने जर्मनी की औद्योगिक क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि वहां की बड़ी कंपनियों के साथ-साथ छोटे और मझोले उद्योगों की ताकत भी काबिल-ए-तारीफ है।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा है। लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है, 18 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन किया है उस संबोधन में लोकसभा सदस्यों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। संसद सदस्यों की सोच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद ने अपने पत्र में कहा है, कि राष्ट्र के नाम संबोधन में संसद की गरिमा और सांसदों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है, कि प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी सांसदों के मतदान और उनकी मंशा को लेकर जो कहा है, वह अवमानना की श्रेणी में आता है। यह बेहद गंभीर मामला है, इस पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। वेणुगोपाल ने अपने पत्र में कहा, यह सिर्फ एक संसद सदस्य के विशेष अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा और संसद की स्वतंत्रता पर गहरा आघात है।

उन्होंने इस पत्र में लोकसभा अध्यक्ष से मांग की है, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस मामले में विशेष अधिकार हनन की कार्यवाही तुरंत शुरू की जानी चाहिए। लगता है कांग्रेस आक्रामक होती चली जा रही है। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है, जिसके कारण उसे विरोध करने के तौर-तरीके नहीं आते थे। जिस तरह से कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए राष्ट्र के संबोधन को सांसदों के विशेष अधिकार से जोड़कर निशाना साधा है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है, कांग्रेस ने लंबे समय तक विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष को न केवल जवाब देना सीख लिया है वरन सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जाता है, यह अच्छी तरह से जान लिया है। सत्ता पक्ष जिस तरह से विपक्षी नेताओं को घेरने के लिए सत्ता एवं संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। लोकतंत्र और कानून के नाम पर विपक्ष को आतंकित करके रखा था।

उससे अब कांग्रेस बाहर निकल रही है। सत्ता पक्ष को वह उसी अंदाज में न केवल जवाब देना सीख गई है, वरन अदालतों में भी सत्ता पक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अदालतों में मुखर होकर अपनी बात कहना, अदालतों के निर्णय सत्ता पक्ष के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग तरह का विरोध अदालत के सामने किया जाने लगा है। आसंदी के सामने भी विपक्ष दिनों-दिन मुखर हो रहा है। इससे सत्ता पक्ष के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं। न्यायपालिका की कुर्सी में बैठे हुए जजों के लिए भी सत्ता पक्ष का समर्थन आंख बंद करके करना मुश्किल हो रहा है। विपक्ष में अब एक नया संगठित बदलाव देखने को मिल रहा है।

सैयद जकी हैदर | सम्पादक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

जेल में आतंकी बनाने की पाठशाला चलाने वाले सात आतंकियों को 7 साल जेल

नई दिल्ली। जेल में आतंकी बनाने की पाठशाला चलाने के मामले में नेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआइए) की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी टी नसीर समेत सात आरोपियों को सात साल जेल की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टी नसीर समेत सभी दोषियों पर 48 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों में टी नसीर के अलावा सैयद सुहैल खान, मोहम्मद उमर, जाहिद तबरेज, सैयद मुदस्सिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी और सलमान खान शामिल हैं। सभी आरोपियों ने पहले ही एनआईए द्वारा दायर आरोपों को स्वीकार कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए के मुताबिक यह पूरा षड्यंत्र बेंगलुरु की प्रप्पना अग्रहर सेंट्रल जेल के अंदर रचा गया था। टी नसीर ने जेल के अंदर बंद कैदियों के बीच कट्टरपंथ फैलाने का काम किया। साजिश के तहत भोले-भाले युवाओं की पहचान कर उन्हें भर्ती करना, प्रशिक्षण देना और आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करना शामिल था। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी बेंगलुरु शहर में आतंकी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे जो लश्कर-ए-तैयबा के भारत विरोधी एजेंडे का हिस्सा था।

एसबीआई रिपोर्ट से खुलासा, कर्ज में डूबे राज्यों की वजह से धीमी पड़ी विकास की रफ्तार

नई दिल्ली। देश के विकास की रफ्तार को लेकर एक तस्वीर सामने आई है। एसबीआई रिसर्च की ताजा रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों को पैसा दे रही है, लेकिन कई राज्य उस पैसे का फायदा नहीं उठा पा रहे। हालात ऐसे हैं कि अगर राज्य खुद आगे बढ़कर खर्च नहीं बढ़ाते, तो विकास की रफ्तार अधूरी ही रह जाएगी। रिपोर्ट से पता चलता है कि सिर्फ केंद्र की मदद से काम नहीं चलेगा, राज्यों को भी जेब ढीली करनी होगी, तभी असली विकास दिखेगा। बता दें पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने एसएएससीआई योजना के तहत राज्यों को करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए दिए। इससे राज्यों का पूंजीगत खर्च जरूर बढ़ा और अर्थव्यवस्था को सहारा मिला, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। पहले जहां सभी राज्य इस फंड का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं अब कई राज्यों के बीच फर्क नजर आने लगा है। कहीं पैसा सही से लग रहा है, तो कहीं काम अटक रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 और 2024-25 के आंकड़ों में कई राज्यों के बीच एसएएससीआई उपयोग दर में बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। कुछ राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कई अन्य पीछे छूट गए हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब ने 2023-24 में केवल 6.5फीसदी का उपयोग किया, जबकि मणिपुर की दर 35.7फीसदी और त्रिपुरा की 73.8फीसदी रही। वहीं, पश्चिम बंगाल ने 2024-25 में 96.7फीसदी और मध्य प्रदेश ने 94.3फीसदी का उपयोग कर बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारत कभी भी आतंक के सामने नहीं झुकेगा: पीएम

हम सब दुःख और संकल्प में एकजुट हैं
पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर पीएम मोदी ने पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

एजेंसी। नई दिल्ली

पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी पर पीएम मोदी ने पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 22 अप्रैल, 2025 को हुए इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। हमले की पहली बरसी पर एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि वह पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हैं। उन्होंने लिखा- पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की याद आ रही है। उन्हें कभी नहीं भुलाया जाएगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं क्योंकि वे इस नुकसान से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम दुःख और संकल्प में एकजुट हैं। भारत कभी भी किसी भी प्रकार के आतंक के सामने नहीं झुकेगा। आतंकवादियों के घृणित मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। पिछले साल 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसके जवाब में भारत ने भी 7 मई को एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई आतंकी बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर हमला किया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया। पहलगाम हमले की पहली बरसी की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना ने मंगलवार को आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जब मानवता की सीमाएं पार हो जाती हैं, तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक आदिल भी था जिसने आतंकियों से जूझते हुए अपनी जान गंवाई थी।

राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री समेत नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की बरसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत शीर्ष नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने एक्स संदेश पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उस जघन्य कृत्य में निर्दोष लोगों की जान जाने का दुखद हादसा हमारी सामूहिक स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। आतंकवाद के ऐसे कृत्य शांति और एकता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को डिगा नहीं सकते। हर जगह और हर रूप में आतंकवाद को हराने के अपने संकल्प पर दृढ़ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्राण गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस अमानवीय और कायराना हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं। राष्ट्र की स्मृति में वे लोग सदैव जीवित रहेंगे।

पश्चिम एशिया संकट: भारतीय नाविक सुरक्षित, घरेलू एलपीजी सप्लाई और ईंधन-गैस वितरण निर्बाध

एजेंसी। नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान-अमेरिका और इजराइल संघर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि पेट्रोलियम और गैस सप्लाई में आ रही अड़चनों के बावजूद देश में तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य है। साथ ही दावा किया है कि जल मार्ग से देश से बाहर ढुलाई का कार्य कर रहे सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य स्तर पर लौट आई है और ईंधन-गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में रोजाना अंतर मंत्रालयी पत्रकार वार्ता में बताया कि पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज पर कोई घटना दर्ज नहीं हुई है और हमारे नाविक सुरक्षित हैं। भारतीय ध्वज वाला क्रूड ऑयल टैंकर देश की सीमा में 18 मार्च को सुरक्षित रूप से प्रवेश कर चुका है और 31 भारतीय नाविकों के साथ आज शाम मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। मंत्रालय अब तक 2,615 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी करा चुका है, जिनमें पिछले 24 घंटों में 25 नाविक शामिल हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा

कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य स्तर पर लौट आई है। अप्रैल में एक लाख टन से अधिक एलपीजी की आपूर्ति की गई है और एक लाख से अधिक सिलेंडर वितरण में हैं। सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा दे रही है और कनेक्शन व अवसंरचना में तेजी से वृद्धि हो रही है। नए एलपीजी ग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है और रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं। हाल ही में हजारों छापेमारी की गई हैं और सिलेंडर जब्त किए गए हैं। तेल विपणन कंपनियां भी जमाखोरी और अवैध बिक्री रोकने के लिए आकस्मिक निरीक्षण कर रही हैं। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की संयुक्त सचिव निधि केसरीवानी ने कहा कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) ने ईंधन और गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश जारी किए हैं। 41 बायोगैस सिलेंडर भराई और भंडारण संयंत्रों को मंजूरी दी गई है तथा 14 संयंत्रों को लाइसेंस प्रदान किया गया है। मिट्टी के तेल की मांग को देखते हुए अस्थायी भंडारण छूट दी गई है, जिसमें 2,500 लीटर तक उच्च गुणवत्ता वाले मिट्टी के तेल और एकबारगी 5,000 लीटर पीडीएस मिट्टी के तेल के भंडारण की अनुमति दी गई है।

मालेगांव ब्लास्ट केस में बड़ा मोड़: बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को किया बरी

मुंबई। वर्ष 2006 के बहुचर्चित मालेगांव ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने इनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को रद्द कर दिया, जिसके साथ ही इन आरोपियों पर चल रहा मुकदमा भी समाप्त हो गया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चांदक की डिवीजन बेंच ने यह फैसला आरोपियों द्वारा दायर अपीलों पर सुनाया। इन अपीलों में सितंबर 2025 में विशेष अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोप तय किए गए थे। अदालत ने न केवल आरोप तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए तर्कों को स्वीकार किया, बल्कि मामले में सह-आरोपियों को पहले ही बरी किए जाने के पहलू को भी ध्यान में रखा।

नेपाल में बालेन शाह के हनीमून पीरियड में ही शुरु हो गया व्यापक जनआक्रोश, सड़क पर लोग

एजेंसी। काठमांडू

नेपाल में बालेन शाह की सरकार बनने के मात्र एक माह के भीतर ही व्यापक जनआक्रोश देखने को मिल रहा है। काठमांडू के मेयर से देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे शाह के लिए सत्ता की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। दो-तिहाई बहुमत के बावजूद उनकी सरकार को सड़कों से लेकर प्रशासनिक केंद्र 'सिंघा दरबार' तक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जानकार के मुताबिक 6 माह का समय किसी भी सरकार के लिए हनीमून पीरिड होता हैं, लेकिन बोलेन के खिलाफ सड़कों पर उतरा यह जनसैलाब बताता हैं कि वे अपने किए गए वादों पर खरे उतरते नहीं दिख रहे है। इस विरोध का सबसे बड़ा कारण भारत से आने वाले सामान पर लगाया गया नया अनिवार्य सीमा शुल्क है। नेपाल सरकार के फैसले के तहत 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर शुल्क लगाया जा रहा है, जिससे खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों के निवासी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं। इसके बाद यह नीति उनके लिए आर्थिक बोझ बन गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने यह निर्णय लेते समय जमीनी वास्तविकताओं को नजरअंदाज किया है, जिससे आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा छात्र संगठनों से जुड़ा है। बालेन शाह सरकार पर आरोप है कि उसने राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संघों को दरकिनार करने या कमजोर करने की कोशिश की है।

अरब सागर में बढ़ी हलचल: भारत ने नोटम के बीच दिखाया दम, पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव

एजेंसी। नई दिल्ली

अरब सागर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों के कारण चर्चा में है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा 200 किलोमीटर क्षेत्र के लिए 'नोटिस टू एयर मिशन' (नोटम) जारी कर मिसाइल परीक्षण की घोषणा के बाद भारत ने भी 400 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र के लिए अपना नोटम जारी कर रणनीतिक जवाब दिया है। पाकिस्तान ने 20 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मिसाइल परीक्षण के लिए संबंधित क्षेत्र में हवाई और समुद्री गतिविधियों पर प्रतिबंध का अलर्ट जारी किया था। इसके जवाब में भारत ने 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक के लिए विस्तृत परीक्षण कार्यक्रम घोषित किया, जिससे क्षेत्र में सैन्य हलचल और बढ़ गई है। इसी बीच भारतीय सेना ने उस इलाके के करीब अपनी ताकत का प्रदर्शन

मिसाइल परीक्षण अलर्ट और 'ऑपरेशन सिंदूर' के अभ्यास से क्षेत्र में बढ़ी सतर्कता

करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत जल-आधारित सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में विशेष यूनिट्स ने उथले जल क्षेत्रों में तेज और सटीक ऑपरेशन कर अपनी तैयारियों का प्रदर्शन किया। अत्याधुनिक असॉल्ट बोट्स के जरिए सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में भी तेजी से मूवमेंट और कार्रवाई की क्षमता दिखाई। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे अभ्यास भारतीय सेना की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इन अभियानों का उद्देश्य न केवल सैनिकों की दक्षता बढ़ाना है, बल्कि किसी भी संभावित खतरे के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना भी है। दोनों देशों द्वारा लगभग एक ही समय में जारी किए गए नोटम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। ये अलर्ट नागरिक विमानन और समुद्री यातायात को निर्धारित क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए जारी किए जाते हैं, ताकि परीक्षण के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना या भ्रम की स्थिति न बने। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान द्वारा चिन्हित परीक्षण क्षेत्र एक-दूसरे की समुद्री सीमाओं के अपेक्षाकृत करीब हैं, जो इस स्थिति को और संवेदनशील बनाता है। हालांकि, दोनों देश नियमित रूप से अपनी सैन्य तैयारियों के तहत मिसाइल परीक्षण करते रहते हैं और यह अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत पूर्व सूचना देकर किया जाता है।

ख़ास ख़बर

अमर कॉलोनी में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या, दुष्कर्म के बाद गला घोंटने की आशंका

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पॉश इलाके अमर कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी की 21 वर्षीय बेटी की घर के भीतर ही हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार, मृतका 1997 बैच के आईआरएस अधिकारी की बेटी थी। उसने हाल ही में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और इन दिनों संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रही थी। परिवार के मुताबिक, वह घर पर ही पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में घर के भीतर हुई इस वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात बेहद क्रूर तरीके से अंजाम दी गई। आशंका जताई जा रही है कि पहले युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद मोबाइल चार्जर की तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। मामले में शक की सुई घर के एक पूर्व नौकर पर जाकर टिक गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान का रहने वाला यह नौकर करीब दो महीने पहले तक घर में काम करता था, लेकिन उसके व्यवहार के चलते उसे निकाल दिया गया था। बुधवार सुबह वह अचानक घर के आसपास देखा गया था, जिसके बाद से वह फरार है। घटना की सूचना मिलते ही दक्षिण-पूर्वी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। वहीं, इस घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है।

एलपीजी की कमी को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का सुनवाई से इनकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत के मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये मामला पश्चिम एशिया में जारी संकट से जुड़ा हुआ है और ये सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। कोर्ट इस पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि क्या हम सरकार चला रहे हैं। कोर्ट इस मामले पर दखल नहीं दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले ही एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट लगा चुकी है। ऐसे मामले कार्यपालिका के दायरे में आता है। सरकार और तेल कंपनियां संसाधनों पर निर्भर हैं। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार को एलपीजी के निर्यात पर रोक लगाने का दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं। कोर्ट देश की आर्थिक नीति तय नहीं कर सकती है। क्या कोर्ट ये तय करेगी कि किस चीज का आयात हो और किस चीज का नहीं। कोर्ट ने कहा कि याचिका में एलपीजी के निर्यात का कोई ठोस जिक्र नहीं है। याचिका में कहा गया है कि लाखों लोग घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की अनुपलब्धता की वजह से परेशान हैं। एलपीजी सिलेंडर कालाबाजार में पांच हजार रुपये में बेचा जा रहा है। सरकार एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने में नाकाम रही है। तब कोर्ट ने कहा कि ये सब देखना सरकार का काम है कि सिलेंडरों की आपूर्ति ठीक से हो रही है कि नहीं।

नाज़िया इलाही खान का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से कोई संबंध नहीं: जमाल सिद्दिकी

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दिकी ने एक अखबार में चलाई गई ख़बर का खंडन किया। खबर में नाज़िया इलाही खान को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का नेता बताया जा रहा है। मोर्चा के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि नाजिया इलाही खान का मोर्चे से कोई संबंध नहीं है। बुधबार को मीडिया को जारी बयान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दिकी ने कहा कि नाजिया इलाही खान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में नहीं है। न प्रदेश की टीम और न राष्ट्रीय टीम में, उनके पास अल्पसंख्यक मोर्चा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जमाल सिद्दिकी ने कहा कि उनके जितने भी बयान होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ निजी बयान होते हैं, उसका भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। उनके बयानों से अल्पसंख्यक मोर्चा की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि नाजिया इलाही खान के किसी भी तरह के बयानों को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से नहीं जोड़ा जाए। उन्होंने नाजिया को चेतावनी दी है कि अगर वो भविष्य में खुद को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी बताएंगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमाल सिद्दिकी का कहना है कि इनके बयान "आपत्तिजनक, नफरत फैलाने वाले और असंवैधानिक" होते हैं, जिनके द्वारा धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जाती है।

मंत्री प्रवेश साहिब ने कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, बोले- विकास केवल घोषणाओं से नहीं होता

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बुधवार को पालम और निलोठी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में जल निकासी, सड़क संपर्क और जल एवं सीवर सेवाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। मंत्री प्रवेश साहिब ने कहा कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं होता बल्कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने से होता है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इन कार्यों के अंतर्गत पालम लिंक ड्रेन के तटबंधों को मजबूत करना, पालम क्षेत्र में चार आरसीसी बॉक्स कलवर्ट पुलों का निर्माण, निलोठी के पास कनेक्टिविटी सुधार के लिए एक नए डबल-लेन पुल और नजफगढ़ ड्रेन के साथ सड़क का पुनःनिर्माण शामिल है। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि इसके अतिरिक्त लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली जल बोर्ड की एक महत्वपूर्ण परियोजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत महावीर एन्क्लेव, रामफल चौक, मधु विहार और साध नगर में नई पानी और सीवर लाइनों का विस्तार किया जाएगा। इससे इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही पानी और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। मंत्री प्रवेश ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं मिलकर आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं- जैसे जलभराव, ट्रैफिक जाम और बुनियादी सुविधाओं की कमी- को दूर करने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि पालम लिंक ड्रेन को मजबूत करने से मानसून के दौरान बाढ़ और ओवरफ्लो की समस्या में कमी आएगी। वहीं, नए बनाए गए कलवर्ट पुलों से स्थानीय आवागमन आसान होगा और क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। निलोठी में नए पुल और सड़क के पुनर्निर्माण से आसपास की कॉलोनियों के लिए यातायात सुगम होगा, जिससे लोगों की दैनिक यात्रा अधिक सुरक्षित और सहज बनेगी। मंत्री ने कहा कि हर खर्च किया गया रुपया गुणवत्ता वाले काम में दिखना चाहिए। हम समय पर काम पूरा करने और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

डीएमआरसी ने पीतमपुरा–प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का प्रस्ताव किया तैयार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने पीतमपुरा–प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन तक प्रशांत विहार और रोहिणी क्षेत्र की ओर से बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आउटर रिंग रोड पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण का एक प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को भेजा गया है। यह जानकारी बुधवार को दिल्ली विधानसभा की ओर से जरिए एक विज्ञप्ति में दी गई है। यह पहल दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद सामने आई है। उन्हें विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ, प्रशांत विहार से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में मजलिस पार्क–दीपाली चौक कॉरिडोर के तहत प्रशांत विहार की ओर से मेट्रो स्टेशन तक सुरक्षित और सीधी पहुंच के अभाव को प्रमुखता से उठाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय द्वारा डीएमआरसी को लिखे गए पत्र में इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। पत्र में यह उल्लेख किया गया कि वर्तमान में स्टेशन तक पहुंच केवल पीतमपुरा की ओर से उपलब्ध है, जिससे स्थानीय निवासियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। डीएमआरसी ने अपने उत्तर में बताया कि फुट ओवर ब्रिज का प्रस्ताव तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मौजूदा पीडब्ल्यूडी फ्लाईओवर के नीचे आवश्यक ऊंचाई (हेडरूम) सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) और राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के मानकों के अनुसार सड़क संरचना में कुछ बदलाव करने होंगे। प्रस्ताव फिलहाल पीडब्ल्यूडी के पास स्वीकृति के लिए लंबित है और आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, डीएमआरसी ने पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए एंट्री/एग्जिट-1 के पास जेब्रा क्रॉसिंग, बेहतर मार्ग व्यवस्था और ग्राउंड लेवल से कॉनकोर्स स्तर तक लिफ्ट सुविधा जैसे उपाय भी प्रस्तावित किए हैं। ये सभी उपाय स्टेशन के मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन प्लान का हिस्सा हैं, जिसे यूटीटीआईपेक को स्वीकृति के लिए भेजा गया है और स्वीकृति के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रस्तावित कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि बुनियादी ढांचा पूर्णतः सुरक्षित, समावेशी और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो। उन्होंने कहा कि मेट्रो जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का लाभ तभी सार्थक होता है, जब हर नागरिक, विशेषकर हमारे वरिष्ठ नागरिक बिना किसी कठिनाई के इसका उपयोग कर सकें। उनकी सुविधा और गरिमा का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है।

'ग्राम-2026' रोडशो: नई दिल्ली में राजस्थान की कृषि क्रांति का बिगुल, निवेश और साझेदारी के नए द्वार खुलेंगे"

23 अप्रैल को भव्य आयोजन, एग्रीटेक नवाचार पर होगा वैश्विक मंथन

लोकतंत्र की शान

जयपुर/नई दिल्ली। राजस्थान को कृषि नवाचार और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) तथा राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा 'ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)–2026' रोडशो का भव्य आयोजन गुरुवार 23 अप्रैल को नई दिल्ली में किया जा रहा हैं। यह रोडशो राज्य की प्रगतिशील कृषि नीतियों, निवेश अवसरों और एग्रीटेक क्षेत्र की अपार संभावनाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकाने का सुनहरा अवसर साबित होगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट–2026 के दिल्ली रोड शो में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, भूटान, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, इजिप्ट, इथियोपिया, फिजी, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, कज़ाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, वियतनाम आदि दूतावासों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

GRAM 2026 GLOBAL RAJASTHAN AGRITECH MEET 23 May - 25 May 2026, Jaipur

भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 22 से 26 सितंबर को, जलवायु और जल प्रबंधन पर फोकस

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। जल शक्ति मंत्रालय ने घोषणा की है कि 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 (इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक-आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू) 22 से 26 सितंबर तक यहां भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय जलवायु-संवेदनशील जल प्रबंधन होगा, ताकि बाढ़, अनियमित वर्षा और जल संकट जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। कार्यक्रम में जल संरक्षण, कुशल उपयोग और सतत प्रबंधन पर चर्चाएं होंगी। इस अवसर पर बुधवार को यहां श्रम शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आधिकारिक रूप से इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का शुभारंभ किया। पाटिल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस दौरान दूसरी इंटरनेशनल वॉश कॉन्फ्रेंस भी 22 से 24 सितंबर तक समान स्थल पर आयोजित होगी। इसमें विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि जल उपलब्धता लगातार घट रही है इसलिए उपभोग कम करना, संरक्षण बढ़ाना और जल संचयन को व्यापक स्तर पर लागू करना आवश्यक है। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों पर जोर देते हुए कहा कि जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विस्तार से जल संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। सरकार नदियों और जलाशयों की सेहत सुधारने के लिए कई परियोजनाएं चला रही है, जिनमें यमुना नदी और अमृत सरोवरों का विकास शामिल है। साथ ही जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है ताकि सभी ग्रामीण घरों तक नल का जल पहुंच सके। जल संसाधन विभाग के सचिव वीएल कंठा राव ने कहा कि यह पहली बार है जब कार्यक्रम को इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक नाम दिया गया है। इस बार अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और भी व्यापक होगी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में तकनीकी सत्र, प्रदर्शनी और फील्ड विजिट शामिल होंगे।चर्चाओं में शासन, संसाधन अनुकूलन, तकनीक का उपयोग, सामुदायिक भागीदारी, जलवायु जोखिम प्रबंधन और वित्तीय तंत्र जैसे विषयों पर विचार किया जाएगा।

लोकसभा की 543 सीटों पर 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस का देशव्यापी पोस्टकार्ड अभियान शुरू

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः महिला कांग्रेस ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तुरंत लागू करने की मांग को लेकर देशव्यापी पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है। मई और जून में दो महीने निरंतर चलने वाले इस अभियान के तहत देश की करीब 10 लाख महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड भेजेंगी। इनमें मांग की जाएगी कि जुलाई में संसद के मानसून सत्र में विशेष प्रस्ताव लाकर लोकसभा की 543 सीटों पर ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया जाए और इसमें एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं के साथ ओबीसी महिलाओं को भी शामिल किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने महिला आरक्षण लागू न किए जाने और देशभर में बढ़ते महिला अपराधों के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित प्रदेशों में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। अलका लांबा ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देशभर में झूठ फैला रही है, लेकिन कांग्रेस सच्चाई के साथ उस झूठ को बेनकाब कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र के पहले दिन भी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर इसे तुरंत लागू करने की मांग की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को धोखा बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने दावा किया कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, जबकि असलियत में वह परिसीमन बिल था, जिसे गिराकर विपक्ष ने देश के संविधान को बचाने का काम किया।

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में सीखने के परिणामों में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं: यूनेस्को चेयर प्रतिनिधि

» **डॉ. राहुल मेहरा ने नीति-निर्माताओं से छात्र स्वास्थ्य को शिक्षा का आधार मानने की अपील की, न कि एक समानांतर प्राथमिकता**

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली, भारत — जैसे-जैसे भारत बुनियादी शिक्षा और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के प्रयास तेज कर रहा है, यह समझ बढ़ रही है कि छात्र स्वास्थ्य शैक्षणिक सफलता का एक महत्वपूर्ण लेकिन अभी तक कम ध्यान दिया गया निर्धारक है। शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि छात्रों के स्वस्थ व्यवहार और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच गहरा संबंध है। यूनेस्को चेयर ऑन ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन के भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधि और तरंग हेल्थ एलायंस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राहुल मेहरा ने व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को शिक्षा प्रणाली का एक मुख्य हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। डॉ. मेहरा ने छात्र सीखने में बाधा डालने वाली तीन परस्पर जुड़ी चुनौतियों की पहचान की, जिन्हें अक्सर शिक्षा नीति में नजरअंदाज किया जाता है। पहला, पोषण की कमी—विशेषकर एनीमिया—जो संज्ञानात्मक विकास और शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करती है। दूसरा, बढ़ती निष्क्रिय जीवनशैली और स्क्रीन टाइम, जो बच्चों को मोटापा, मधुमेह और

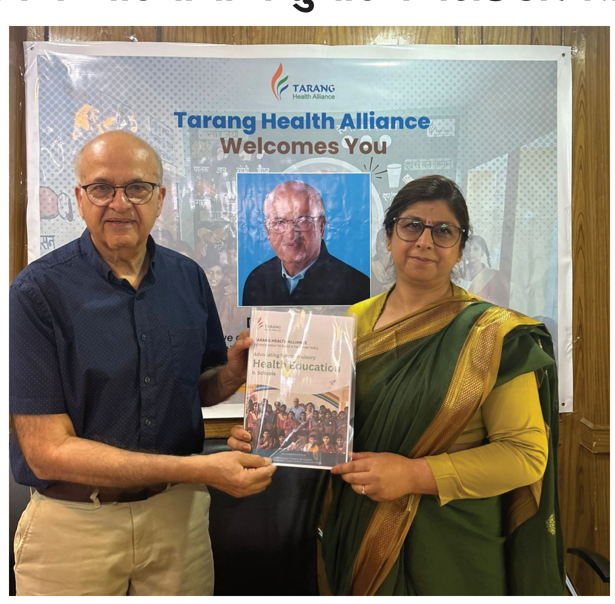

अन्य गैर-संचारी रोगों के शुरुआती जोखिम में डाल रही है। तीसरा और तेजी से बढ़ता हुआ संकट है मानसिक स्वास्थ्य का, जिसमें कई छात्र लगातार तनाव, चिंता और कम भावनात्मक स्थिरता का सामना कर रहे हैं—जो सीखने और सहभागिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, डॉ. मेहरा ने बताया कि लगभग 50 प्रतिशत स्कूली बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं—जो संज्ञानात्मक विकास में कमी, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में गिरावट और स्मृति में कमी से जुड़ा हुआ है। किशोरों में, विशेष रूप से लड़कियों में, यह आंकड़ा लगभग 60 प्रतिशत तक है। वहीं, लगभग 20 प्रतिशत छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखी जाती हैं।

तरंग हेल्थ एलायंस के बारे में- तरंग हेल्थ एलायंस एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो प्रमाण-आधारित स्कूल स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत के युवाओं के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। डॉ. राहुल मेहरा के नेतृत्व में, संगठन ने हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़ और जयपुर के सरकारी और निजी स्कूलों में व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किए हैं। इस पहल में मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए संरचित स्वास्थ्य पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी के ढांचे शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री मांडविया जम्मू-कश्मीर में 30 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का शुक्रवार को करेंगे उद्घाटन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 24 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के ओमपोरा में नवनिर्मित 30 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि डॉ. मांडविया इस अवसर पर अस्पताल निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। अस्पताल परियोजना लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत से 5 एकड़ भूमि पर निर्मित की गई है। इसमें अस्पताल भवन, सेवा भवन और 32 आवासीय क्वार्टर शामिल हैं, जो लगभग 24,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। प्रारंभ में अस्पताल में 30 बिस्तर होंगे, जिन्हें धीरे-धीरे बढ़ाकर 100 तक किया जाएगा। यह अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे क्षेत्र के 50,000 से अधिक श्रमिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। इस सुविधा में तीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और एक विशेष आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जहां नियोजित और गंभीर दोनों प्रकार की शल्यक्रियाएं की जा सकेंगी। अस्पताल में चार पेशेंट लिफ्ट, आधुनिक एचवीएसी प्रणाली, सौर जल तापन और सीवेज एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र जैसी पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर में ईएसआई योजना 16 अक्टूबर 1989 को शुरू हुई थी, जिसमें प्रारंभ में जम्मू, कठुआ और श्रीनगर के लगभग 7,000 कामगार शामिल थे। वर्तमान में यह योजना पूरे केंद्रशासित प्रदेश में लागू है और लगभग 1,83,119 बीमित व्यक्ति तथा 7 लाख लाभार्थी इससे लाभान्वित हो रहे हैं।प्रदेश में चिकित्सा लाभ वितरण प्रणाली श्रीनगर, कठुआ, कटरा, सांबा और उधमपुर स्थित पांच औषधालय सह शाखा कार्यालयों और आठ ईएसआईएस औषधालयों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देती है। माध्यमिक देखभाल सांबा के बारी-ब्राह्मणा स्थित 50 बिस्तरों वाले ईएसआईसी मॉडल अस्पताल में उपलब्ध है। इसके अलावा सुपर-स्पेशियलिटी उपचार के लिए 15 निजी नर्सिंग होम, अस्पताल और निदान केंद्रों के साथ सह-व्यवस्थाएं भी की गई हैं। नकद लाभ जम्मू और अन्य जिलों में स्थित शाखा कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं।

उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद भाजपा ने ममता का मांगा इस्तीफा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कोयला घोटाले की जांच करने गए अधिकारियों को रोकने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद उनका इस्तीफा मांगा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगलराज और अराजकता का बोलबाला है और कानून-व्यवस्था पूरी तरह विफल है। न्यायालय की टिप्पणी के बाद ममता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना कर उन्हें काम करने से रोका इस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य में इस तरह की अराजक व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है लेकिन ममता मस्त हैं। ममता ने जनता को ठगा है। राज्य की जनता त्रस्त है। जनता सोच नहीं सकती थी कि उनकी मुख्यमंत्री रक्षक से भक्षक बन गई है। उन्होंने कहा कि कल पश्चिम बंगाल में चुनाव है। राज्य की जनता इस बार बदलाव के लिए वोट करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में संदेशखाली में जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा है, ममता ने कुछ नहीं किया। राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं। पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को इस बार सबक सिखाएगी। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने आई-पैक ऑफिस में ईडी की रेड के दौरान मुख्यमंत्री बनर्जी के कथित हस्तक्षेप को 'लोकतंत्र के लिए खतरा' बताते हुए कड़ी फटकार लगायी। जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच ने इसे केंद्र-राज्य का नहीं बल्कि व्यक्तिगत कृत्य का विवाद बताया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सिस्टम को चुनौती नहीं दे सकता।

संक्षिप्त समाचार

जिलाधिकारी,पुलिस अधीक्षक, द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में गोष्ठी का आयोजन किया गया

» आगामी होमगार्ड भर्ती/परीक्षा को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई

लोकतंत्र की शान : मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर, जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों के प्रधानाचार्य/प्रिंसिपल, नामित मजिस्ट्रेट तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी के दौरान परीक्षा की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा सभी अधिकारियों को उनके दायित्वों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों की सक्रिय निगरानी, प्रवेश पत्रों की गहन जांच तथा संदिग्ध व्यक्तियों/गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने, अभ्यर्थियों को समय से परीक्षा केन्द्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। अंत में सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए गए, जिससे परीक्षा सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराई जा सके ।

महिला बिल के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बड़ा हादसा टला

मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, मुरादाबाद के कोतवाली क्षेत्र स्थित इंपीरियल चौराहे पर महिला बिल के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। अखिल भारतीय हिंदू परिषद द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब महिला प्रदेश अध्यक्ष के दुपट्टे में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान सपा का झंडा जलाया जा रहा था, तभी चिंगारी महिला नेता के दुपट्टे पर जा गिरी और उसमें आग लग गई। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत महिला को अलग किया और आग बुझाई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना में रीता नाम की महिला बाल-बाल बच गई। पुलिस की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से उसकी जान सुरक्षित रही। घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन हालात जल्द ही नियंत्रण में आ गए। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के प्रदर्शनों के दौरान सतर्कता बरतें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

दो सभासदों में हुई मारपीट, एक पर मारपीट व धमकी का केस दर्ज

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः बुधवार को हसनपुर नगर पालिका परिषद के दो सम्मानित सभासदों के बीच मारपीट का मामला सामने आया एक सभासद की तहरीर पर दूसरे सभासद पर गाली गलौज मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है, वहीं पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, बुधवार को लालबाग बजरिया निवासी शाहनवाज अंसारी पुत्र रफीक अहमद ने बताया कि 21 अप्रैल की शाम करीब सात के बीच यह घटना घटी उन्होंने बताया कि वह अपने आजाद मार्केट साइट से लौट रहे थे शाहनवाज के अनुसार संभल अड्डा चौराहा पर दूसरे वार्ड के सभासद जाहिद अली पुत्र अब्दुल वाहिद ने उनकी बाइक रोक ली जाहिद ने कथित तौर पर गंदी गालियां देते हुए कहा कि पालिका के सभी काम शाहनवाज के वार्ड में हो रहे हैं जब शाहनवाज ने गाली देने का विरोध किया तो जाहिद अली ने शाहनवाज का गिरेबान पकड़ कर लात घुसो और थप्पड़ों से उनकी पिटाई कर दी इस दौरान उनकी बाइक भी गिर कर क्षतिग्रस्त हो गई शाहनवाज को पीटता देखा रास्ते से गुजर रहे जावेद पुत्र जरीफ अहमद निवासी मोहल्ला लालबाग ऊंचा और हसन अलीपुर मोहम्मद असलम निवासी मोहल्ला लालबाग रेतीया सहित अन्य लोग मौके पर जमा हो गए उन्होंने बीच बचाव का पीड़ित को बचाया वही इस संबंध में कोतवाल राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि सभासद शाहनवाज अंसारी की तैहरीर के आधार पर आरोपी जाहिद अली के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच उपरांत विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी 1

मुरादाबाद मंडल के तीन जिलों में 7% की जगह 3% का ब्याज ही लिया जाए : चंद्र प्रकाश शर्मा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः मंगलवार को जनपद अमरोहा के विकास खण्ड हसनपुर में भारतीय किसान संघ ने मुरादाबाद मण्डल के तीन जिलों अमरोहा, मुरादाबाद और सम्भल में सहकारी समितियों के माध्यम से लिए जाने वाले ऋण पर 7%ब्याज लिए जाने का तहसीलदार के माध्यम से मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ को ज्ञापन सौंपा, तथा सरकार से मांग की है कि अन्य जिलों की तरह 3% ब्याज लेकर ही वसूली की जाय और अब तक लिया गया 7% ब्याज का 4% शीघ्र वापिस किया जाए, वही उन्होंने कहा कि कार्ड को रिन्यूअल करने के नाम पर बैंकों में हो रही अवैध वसूली को शीघ्र रोक जाए , साथ ही किसानों के अंश बंटवारे में लेखपालों द्वारा जल्दबाजी में की गई कमियों को गांव गांव कैम्प लगवाकर ठीक कराया जाए, इस अवसर पर प्रांतीय गन्ना प्रमुख महीपाल सिंह, जिला अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष राष्ट्र सेवी संगठन के संयोजक कृष्ण कुमार शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष धर्मपाल सिंह चौहान, जिला युवा प्रमुख लाखन सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान, ब्लॉक उपाध्यक्ष कामेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, गंगाराम, मंत्री जगदीश सिंह, सहमंत्री गुड्डू सिंह आदि किसान भाई मौजूद रहे 1

2 मई से हसनपुर में श्रीमद् भागवत कथा की होगी अमृत वर्षा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः नगर में श्रीमद् भागवत कथा 2 मई 2026 से प्रारंभ होगी जो 8 मई 2026 तक चलेगी, बता ते चले कि नगर के झारखंड महादेव शिवाला मंदिर परिसर में 2 मई से 8 मई तक श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा कथा वाचिका पूज्य सिद्धि पूनम जी श्री धाम बरसाना के श्री मुख से होगी वही आयोजको ने बताया कि 1 मई को प्रातः 9:00 बजे से कलश यात्रा निकलेगी जिसमें 108 महिलाएं सिरों पर कलश धारण करके निकलेंगी तथा संपूर्ण नगर में भ्रमण के बाद कलश स्थापित होगा, वही 2 मई से कथा का प्रारंभ झारखंड महादेव शिवाला मंदिर परिसर में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा, वहीं उन्होंने बताया कि 2 मई से 8 मई तक श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा होगी वहीं 9 मई 2026 को प्रातः 9:00 बजे से पूर्ण आहुति एवं प्रसाद का वितरण किया जाएगा 1

शिक्षक राकेश कुमार को लखनऊ में मिला उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

लखनऊ/ हसनपुरः मंगलवार को हसनपुर के अलीपुर खादर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राकेश कुमार को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया इस इस संबंध में विद्यालय प्रधानाध्यापक और अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ हसनपुर होमपाल सिंह ने बताया कि रानी लक्ष्मी बाई मेमोरियल स्कूल इंदिरा नगर लखनऊ में आयोजित हुए उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में कंपोजिट विद्यालय अल्लीपुर खादर और राकेश कुमार को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया होमपाल सिंह ने बताया कि यह हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि विद्यालय स्टाफ की मेहनत से कंपोजिट विद्यालय अल्लीपुर खादर आज लखनऊ तक सम्मानित हो रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आय में योजना का आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा बच्चों को किताबें ,शिक्षण सामग्री मॉडल पेपर से लेकर उनको अभिभावकों से बात करके छुट्टियों के दिनों में भी पढ़ना और बच्चों को परीक्षा केंद्र तक ले जाना और परीक्षा के पश्चात सब वापस घरों तक छोड़ना।ये सारी व्यवस्था की गई और इसके परिणामस्वरूप आज हमने सर्वाधिक 8 बच्चों का चयन देकर जनपद में सर्वश्रेष्ठ परीक्षाफल दिया है ।प्रधानाध्यापक होमपाल सिंह ने विद्यालय को सम्मान मिलने पर समस्त विद्यालय स्टाफ, बच्चों और ग्रामवासियों को बधाई दी और बताया कि भविष्य में और अच्छा परीक्षाफल देते रहेंगे। इसके साथ ही सभी से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा नामांकन कंपोजिट विद्यालय अल्लीपुर खादर में कराकर अच्छी शिक्षा और मजबूत भविष्य की नींव रखें।

सपा ने युवा चेहरे पर जताया भरोसा हनी फैसल बने बिजनौर जिलाध्यक्ष

नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह, संगठन को मजबूत करने की उम्मीद

लोक तंत्र की शान, खिज़र अहमद

जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूरे जिले में कई के चेहरे उतरे रुचि वीरा के करीबी माने जाते है हनी फैसल

बिजनौर। समाजवादी पार्टी ने जनपद बिजनौर में संगठन को नई दिशा देने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लेते हुए युवा नेता हनी फैसल को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी नेतृत्व के इस निर्णय को संगठन में नई ऊर्जा और मजबूती लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। हनी फैसल को जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। समर्थकों ने खुशी जाहिर करते हुए इसे युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने वाला फैसला बताया है। उनका कहना है कि हनी फैसल के नेतृत्व में संगठन को नई गति मिलेगी और पार्टी जनपद में और अधिक मजबूत होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को सक्रिय और प्रभावी बनाने के लिए यह नियुक्ति की गई है। वहीं, हनी फैसल ने अपनी नियुक्ति पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वह सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। समर्थकों का मानना है कि युवा नेतृत्व के जरिए समाजवादी पार्टी को जनपद में नई पहचान और मजबूती मिलेगी।

महिला विरोधी हैं कांग्रेस व सपा के कारनामे : मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को पारित न होने देने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) सहित सभी विपक्षी दलों पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा है। गोरखपुर में विपक्षी दलों पर गरजते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्टियां महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार नहीं देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का इतिहास और उनके कारनामे महिला विरोधी हैं। <सीएम योगी बुधवार शाम योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं का अधिकार बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में जब नया संसद भवन बना तो पीएम ने नए संसद भवन में सबसे पहला अधिनियम नारी शक्ति वंदन का ही पारित कराया। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक के जरिये 2029 के लोकसभा चुनाव से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को कानून बनाने और उसके क्रियान्वयन में भागीदारी का अधिकार देना चाहते हैं लेकिन विधेयक के गिरने पर जश्न मनाने वाले महिला विरोधी विपक्ष को यह मंजूर नहीं है। उन्होंने इसके लिए मुख्य रूप से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा के कारनामे शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं, दलितों, वंचितों, पिछड़ो के अधिकार में हमेशा बाधा डालने का काम किया। जबकि सपा तो घोषित रूप से नारी विरोधी है। सपा के बारे में यह कहा भी जाता है, 'देख सपाई, बिटिया घबराई।'

"योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं"

लोक तंत्र की शान

कोलकाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ममता बनर्जी को ललकारते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को भगवा लहराएगा। उन्होंने इशारों में ममता व अभिषेक बनर्जी पर प्रहार करते हुए कहा कि बुआ-भतीजा बंगाल का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां ऊर्दू चलेगी। कोई माई का लाल बंगाल की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि टीएमसी के जो लोग बंगाली अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें बता दो कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं, मां कालीबाड़ी से है। सीएम योगी जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। यहां आए अधिसंख्य लोग हाथ में पोस्टर लिए हुए थे, जिस पर लिखा था- "योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।"

4 मई को बंगाल में लहराया जाएगा भगवा ध्वज- सीएम योगी ने कहा कि 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। परिवर्तन के प्रति लोगों के हृदय का उद्गार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहले चरण में 80 फीसदी सीटें भाजपा जीतने जा रही हैं। जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल में भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा, बंगाल फिर से 'सोनार बांग्ला' बनकर अपनी पहचान स्थापित करेगा। सीएम ने बड़ा बाजार को सबसे समृद्धतम व्यापारिक क्षेत्र बताते हुए कहा कि व्यापार, साहित्य, कला, सांस्कृतिक परंपरा व पौराणिक कालीबाड़ी मंदिर के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। हमें बंगाल की अस्मिता को बचाना है और कठमुल्लापन को बढ़ावा देने वालों को हर हाल में रोकना है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र ने आपको जो ताकत दी है, अपने वोट के जरिए उसका सही इस्तेमाल कीजिए।

समाजसेवी महताब खा चांद ने नजीबाबाद को जिला बनाने की मांग, प्रधानमंत्री व मुख्य मंत्री को पत्र लिख कर की

» ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक महत्व का हवाला देकर जनहित में उठाई आवाज - पर्यटन, स्वास्थ्य और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

लोक तंत्र की शान, खिज़र अहमद

नजीबाबाद (बिजनौर): ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की नगरी नजीबाबाद को जिला घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। इस संबंध में प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को पत्र भेजकर नजीबाबाद को जनपद बनाने की मांग की गई है। पत्र में बताया गया कि उत्तराखंड की सीमा से सटा नजीबाबाद भौगोलिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह नगर कोटद्वार, हरिद्वार सहित किरतपुर, नगीना, बढ़ापुर, नहटौर, धामपुर, स्योहारा और नूरपुर जैसे प्रमुख कस्बों से सीधे सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। साथ ही इन क्षेत्रों के लिए रेल सेवा भी सुचारू रूप से उपलब्ध है, जिससे यह क्षेत्र पहाड़ी और मैदानी इलाकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है।

ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व–नजीबाबाद का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। इसे महर्षि कण्व की तपोस्थली, दुष्यंत-शकुंतला की प्रणय स्थली और राजा भरत की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यहां स्थित मोरध्वज किला, पत्थरगढ़ किला और विश्व प्रसिद्ध दरगाह आलिया नजफे हिन्द इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को और मजबूत करते हैं। यह भूमि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साहित्यकारों, पत्रकारों और शायरों की भी रही है।

विकास से वंचित रहने का आरोप–मांग करने वालों का कहना है कि आजादी के बाद से नजीबाबाद के साथ लगातार उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया गया है, जिसके चलते यह क्षेत्र उद्योग, रोजगार और बुनियादी विकास से अछूता रह गया। उदाहरण के तौर पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की स्थापना हरिद्वार में और मेडिकल कॉलेज को बिजनौर के पास स्थापित किया जाना नजीबाबाद के साथ हुए भेदभाव के रूप में देखा जा रहा है।

पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाओं की संभावनाएं–नजीबाबाद चारधाम यात्रा के प्रमुख मार्गों में शामिल है, जिससे हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आवागमन होता है। यदि इसे जिला बनाया जाता है, तो यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ चिकित्सा सुविधाओं में भी सुधार होगा। मांगकर्ताओं ने पत्थरगढ़ किले में एम्स जैसे उच्चस्तरीय मेडिकल संस्थान की स्थापना की भी संभावना जताई है।

प्राकृतिक संसाधन और रणनीतिक महत्व–नजीबाबाद तहसील क्षेत्र में बड़ी मात्रा में वन भूमि मौजूद है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही इसकी रणनीतिक स्थिति इसे प्रशासनिक रूप से एक स्वतंत्र जिला बनाए जाने के लिए उपयुक्त बनाती है।

जनहित में उठी मांग–मांगकर्ताओं का कहना है कि यदि नजीबाबाद को जिला घोषित किया जाता है तो इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और समग्र विकास को गति मिलेगी। साथ ही आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को प्रशासनिक सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द नजीबाबाद को जिला घोषित करने की मांग की है।

भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः मंगलवार को भाकियू शिक्षक प्रकोष्ठ, अमरोहा द्वारा तहसीलदार/जनगणना प्रभारी लकी सिंह हसनपुर को जनगणना 2027 में शिक्षकों की ड्यूटी से संबंधित समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया,ज्ञापन में गर्भवती, दिव्यांग एवं अस्वस्थ शिक्षकों को छूट, शिक्षकों की ड्यूटी कार्यस्थल या नजदीकी क्षेत्र में लगाने, पति-पत्नी में एक की ही ड्यूटी तथा प्रधानाध्यापक को ड्यूटी मुक्त रखने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। तहसीलदार ने सभी बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा विशेष श्रेणी के शिक्षकों को आवेदन के आधार पर राहत देने एवं सभी शिक्षकों की ड्यूटी सेवारत स्थल/ नजदीकी क्षेत्र में लगाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पंकज चाहल(जिला महामंत्री भाकियू शिक्षक प्रकोष्ठ अमरोहा) हेमराज कोहली (ब्लॉक अध्यक्ष गंगेश्वरी), मो असलम संगठन मंत्री, अंचल सिंह, मंजीत सिंह, अजीत सिंह, मनोज मावी, जुबैर आलम, अरविंद कुमार, विपिन यादव सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे।

लखनऊ बख्शी का तालाब स्थित बिहारी जी मंदिर में योगेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में भंडारे का भव्य आयोजन

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

लखनऊ /राजधानी/ धूमधाम से संपन्न हुआ। इस धार्मिक आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और बिहारी जी के जयकारों के साथ भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मंदिर पहुंचकर बिहारी जी के दर्शन किए तथा प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे, जिनमें बख्शी का तालाब अध्यक्ष वेद रतन सिंह ,बब्बू पांडे, प्रदीप सिंह, लक्ष्मी प्रकाश दीक्षित, नागेंद्र बहादुर सिंह, इतेंद्र सिंह चौहान, महामंत्री दिलीप मिश्रा, हरिओम अवस्थी, विपिन सिंह, योगेश शुक्ला, देवेंद्र मिश्रा सहित अन्य गणमान्य व्यापारी शामिल रहे। कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक एवं श्रद्धा-भक्ति के साथ संपन्न हुआ।

ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन का परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह संपन्न

» दीप प्रज्वलन कर अतिथियों ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ

» महिला विंग जिला अध्यक्ष की घोषणा

लोक तंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के नेतृत्व में जिले में एक भव्य परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष विष्णु रस्तोगी के नेतृत्व में समाज के गणमान्य सज्जनों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वर्णकार समाज के लोग उपस्थित रहे।<कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। दीप प्रज्वलन मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल वर्मा, राष्ट्रीय संरक्षक लोकेश अग्रवाल , राष्ट्रीय संरक्षक अंजू अग्रवाल(महिला विंग) ,राष्ट्रीय महामंत्री जया वर्मा (महिला विंग), व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी , नगर पालिका अध्यक्ष सना मामूनशाहके कर-कमलों द्वारा किया गया। इस दौरान मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा गणेश वंदना एवं स्वागत वंदन प्रस्तुत कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया गया। बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया और पूरे पंडाल में तालियों की गूंज सुनाई दी। सम्मान समारोह के दौरान समाज के सभी पदाधिकारियों एवं अतिथियों को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में एकता, संगठन और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर समाज के संगठनात्मक विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में महिला विंग की जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई, जिससे समाज में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को और अधिक बल मिलेगा। कार्यक्रम के अध्यक्षता विष्णु रस्तोगी जिला अध्यक्ष ने की और,कार्यक्रम के अंत में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्णकार समाज को संगठित कर सामाजिक एवं शैक्षिक विकास की दिशा में निरंतर प्रयास किए जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन लवी सक्सेना ने किया जिसमें सारिका रस्तोगी को जिला अध्यक्ष(महिला विंग) और नेहा रस्तोगी को जिला महामंत्री(महिला विंग) आयोजन शांतिपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।। आयोजन में उपस्थित रहे विष्णु रस्तोगी ,विशाल रस्तोगी ,रूपक रस्तोगी सारिका रस्तोगी ,दीपक रस्तोगी, सुनील रस्तोगी, अनिल रस्तोगी, लवी सक्सेना सरिता बिश्नोई मनु सक्सेना, मयंक सक्सेना, कमलेश गुप्ता ,अवनीत कुमार शर्मा, प्रशांत कुमार शर्मा ,यश शर्मा ,पूनम शर्मा ,नीलम रस्तोगीआदि उपस्थित रहे

संक्षिप्त समाचार

गंडक में नहाते 4 लोग डूबे, 2 महिलाओं की मौत, सोनपुर में चौठारी रस्म के दौरान हादसा

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। सारण के सोनपुर थाना क्षेत्र में गंडक नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के चार लोग डूब गए। इनमें से दो महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि दो अन्य की तलाश जारी है। यह घटना बैजलपुर स्थित जगदंबा स्थान के निकट चौठारी रस्म के दौरान हुई। मृतक महिलाओं की पहचान बैजलपुर निवासी जनार्दन सिंह की 42 वर्षीय पत्नी बबीता देवी और पटना के बख्तियारपुर निवासी रवि कुमार की 40 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों महिलाओं को नदी से बाहर निकाला और सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार, जनार्दन सिंह की बेटी की शादी बीते सोमवार को हुई थी। शादी के चौथे दिन चौठारी की रस्म अदा करने के लिए परिवार के सदस्य गंडक नदी में स्नान करने गए थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बाकी डूबे हुए दो व्यक्तियों की खोजबीन गंडक नदी में की जा रही है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और एसडीआरएफ (SDRF) टीम को दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है और लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है।

लापरवाही पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, एसआईटी गठित

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली पुलिस अधीक्षक ने महनार थाना क्षेत्र में एक आभूषण व्यवसायी रंजीत कुमार के घर हुई घटना के बाद दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है, जिसमें समय पर सूचना न देना और वरीय पदाधिकारियों को अवगत न कराना शामिल है, जिससे पुलिस कार्रवाई में देरी हुई।

प्राथमिक जांच के अनुसार, 20-21 अप्रैल 2026 की मध्य रात्रि में डायल 112 पर तैनात एएसआई शुक्लेश कुमार घटना स्थल पर पहुंचे थे। हालांकि, उन्होंने किसी भी वरीय अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी। इसी प्रकार, अपर थानाध्यक्ष उदय कुमार सिंह को भी घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसके बावजूद, उन्होंने आवश्यक सतर्कता नहीं बरती, त्वरित कार्रवाई नहीं की और न ही वरीय अधिकारियों को सूचित किया। वैशाली पुलिस अधीक्षक ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महनार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। यह टीम मामले का खुलासा करने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी, इंस्टाग्राम पर रील भेजकर हुआ प्यार, एनिवर्सरी से एक दिन पहले की दूसरी शादी

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली में एक पति ने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। घटना जन्दाहा प्रखंड स्थित खोपी पंचायत की है। मुकेश कुमार माझी की शादी 4 साल पहले 22 अप्रैल 2022 में संजू कुमारी से हुई थी। मुकेश महाराष्ट्र में काम करता है। इसी दौरान संजू का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से बिटण्टीपुर निवासी वरुण कुमार माझी से हुआ। बातचीत के दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया। पति जब घर आया और उसे प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उसने दोनों की शादी करवा दी। 21 अप्रैल 2026 को बाबा बटेश्वरनाथ मंदिर परिसर में घरवालों के मौजूदगी में संजू और वरुण का विवाह संपन्न हुई। प्रेमी वरुण कुमार ने बताया कि एक महीने पहले इंस्टाग्राम पर हम दोनों की मुलाकात हुई थी। देखते ही देखते हम दोनों को प्यार हो गया। वो मुझे अपना रील भेजती थी मैं उसे अपना रील भेजता है। ऐसे ही हमारी बातें शुरू हुई। हम दोनों की अब शादी हो गई है, तो सब राजी खुशी है। संजू के पहले पति भी खुश है और मेरा परिवार भी। अब हम दोनों साथ जिएंगे और साथ मरेंगे।। संजू कुमारी ने कहा कि इंस्टाग्राम पर प्यार हो ही गया तो हम क्या करें। वरुण हमें अपना रील वीडियो भेजा करते थे। इसी दौरान हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर ही जानते थे। जब सामने से मुलाकात हुई तो दोस्ती प्यार में बदल गई। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इसलिए हम दोनों ने एक साथ रहने का वादा कर लिया। अब हम दोनों की शादी हो गई है, मुझे अब पहले पति के पास नहीं जाना है। मर जाएंगे लेकिन पहले पति के घर नहीं जाएंगे। संजू ने कहा कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर करीब 300 वीडियो था। पति ने वीडियो डिलीट कर दिया था। इसी को लेकर मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। वरुण के दादा ने बताया कि जब पोता शादी कर लिया है। बहु घर आ गई है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। हम उसे अपनी बहू मान चुके है। किसी भी परिवार से कोई गिला शिकवा नहीं है। संजू के पति मुकेश कुमार माझी ने कहा कि मैं अपने छाती पर पत्थर रखकर उसकी खुशी के लिए शादी करवा दी। उसने बताया कि 4 साल पहले 22 अप्रैल को ही संजू से मेरी शादी हुई थी। एक महीने के प्यार के लिए वो मुझे छोड़ दी। इतना कहते ही मुकेश फूटफूट कर रोने लगा। लेकिन पत्नी संजू के चेहरे पर हंसी का कोई ठिकाना नहीं था। वो वरुण के साथ नई जिंदगी को लेकर खुश है।

फर्जी सिम कार्ड, टेलीग्राम बॉट्स का यूज कर डेटा चोरी

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह भारतीय नागरिकों की संवेदनशील निजी जानकारी विदेशी अपराधियों को बेच रहा था। इस हाई-टेक कार्रवाई में पुलिस ने उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों से चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों, फर्जी एपीआई और टेलीग्राम बॉट्स का उपयोग कर देश की सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता के साथ खिलवाड़ कर रहा था। साइबर सिंडिकेट के खिलाफ ऑपरेशन की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 को केंद्रीय जांच एजेंसी से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को जानकारी मिली थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला रिषभ कुमार अपने घर से ही एक अवैध डेटा एक्सचेंज चला रहा है। मामले की गंभीरता और अंतरराष्ट्रीय संलिप्तता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में साइबर थाना, जिला आसूचना इकाई (DIU) और बिहार एसटीएफ (STF) के अधिकारियों को शामिल किया गया। सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी के नेतृत्व और साइबर डीएसपी हिमांशु कुमार की अगुवाई में टीम ने रिषभ कुमार के ठिकाने पर छापेमारी कर उसे धर दबोचा। रिषभ की निशानदेही पर पुलिस ने उसके तीन अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया, जो इस नेटवर्क की अलग-अलग कड़ियों को संभाल रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रिषभ कुमार (मुख्य आरोपी, अहियापुर, मुजफ्फरपुर), दीपक चौधरी उर्फ आशु कुमार (गाजीपुर, उत्तर प्रदेश), सुधांशु कुमार (जाले, दरभंगा, बिहार) और साहिल कुमार (हथौड़ी, मुजफ्फरपुर, बिहार) के रूप में हुई है। पुलिस ने गिरोह के तीन अन्य सदस्यों की भी पहचान कर ली है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने आरोपियों के बैंक खातों में जमा 4 लाख रुपये फ्रीज कराए हैं और कई मोबाइल फोन तथा आईपैड बरामद किए हैं। जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके मुताबिक पकड़े गए गिरोह के सदस्य आम नागरिकों का डेटा जुटाने के लिए OSINT (Open Source Intelligence) टूल्स, फर्जी सिम कार्ड और टेलीग्राम बॉट्स का यूज करते थे। आरोपी अवैध रूप से एपीआई (API) तैयार करते थे, जिसके जरिए वे सरकारी और निजी डेटाबेस तक अनधिकृत पहुंच बनाते थे।

पटना हाई कोर्ट साउंड पॉल्यूशन पर सख्त, थानेदारों से मांगा हलफनामा

रात 9:30 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक

लोकतंत्र की शान , पटना

राजधानी पटना में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर पटना हाई कोर्ट सख्त हो गया है। इस मामले में वकील सुरेंद्र कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शहर के कई थानों के प्रभारी से हलफनामा मांगा है। हाई कोर्ट के रुख को देखते हुए पुलिस ने किसी भी आयोजन में रात 9:30 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर ने पर रोक लगा दी है।

छात्रों की पढ़ाई पर असर, कोर्ट ने लिया संज्ञान: वकील सुरेंद्र कुमार ने याचिका के जरिये कोर्ट को बताया कि ध्वनि प्रदूषण की दिशा में पटना के शहरी इलाके खासकर के पिरबहोर, कदमकुंआ, गांधी मैदान, आलमगंज, मुसलहपुर, जहां स्टूडेंट सबसे ज्यादा रहते हैं, वहां देर रात तक तेज ध्वनि में गाने वगैरह बजते रहते हैं। इससे रात में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। उनकी स्टडी प्रभावित होती है।

कदमकुआं थाना को फटकार: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कदमकुआं थाना क्षेत्र में लापरवाही को लेकर थानेदार को फटकार भी लगाई। साथ ही सभी संबंधित थानों को अपने-अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया। इसके बाद सभी थानेदारों ने हल्फनाम के जरिये अपने अपने क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण रोकने की दिशा में उठाये गए कदम के बारे में अवगत कराया है। साथ ही इसे सख्ती से लागू कराने की भी बात स्वीकार की है।

9:30 बजे के बाद तेज आवाज पर रोक: कोर्ट के रुख को देखते हुए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। अब किसी भी आयोजन में रात 9:30 बजे के बाद तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने की हिदायत दी जा रही है। आयोजकों को पहले से ही इस नियम की जानकारी दी जा रही है।

10 मई को अगली सुनवाई: इस मामले में अगली सुनवाई जस्टिस राजीव राय के कोर्ट में 10 मई होगी। इधर, जिन थानेदारों ने अभी तक हल्फ नाम नहीं दिया है, वो अपने पड़ोस के थानेदारों से कैसे क्या फाइल करनी है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। इससे साफ है कि कोर्ट के रुख ने थानेदारों को सकते में ला दिया है। पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई है और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तेजी दिखाई दे रही है।

तेजप्रताप यादव-प्रशांत किशोर की मुलाकात

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार की राजनीति में मची हलचल, कई मुद्दों सहित भविष्य की रणनीति पर हुई चर्चा

JJD नेता सह राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव और जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुलाकात का वीडियो सामने आया। इस मुलाकात का वीडियो खुद तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। तेजप्रताप यादव ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा।' उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात के दौरान जनहित, भविष्य की राजनीति, जनता की अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर गहन चर्चा हुई।

कई मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ- तेज प्रताप: तेजप्रताप ने इस मुलाकात को केवल औपचारिक बैठक नहीं बताया, बल्कि कहा कि इसमें ऐसे कई मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ जो आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। तेजप्रताप यादव ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि, यह संवाद उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा, जिसने जनसेवा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के उनके संकल्प को और मजबूत किया है। इस मुलाकात को बिहार की बदलती राजनीति के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है। एक ओर तेजप्रताप यादव अपनी अलग राजनीतिक पहचान मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं, दूसरी ओर प्रशांत किशोर राज्य में वैकल्पिक राजनीति की जमीन तैयार कर रहे हैं।

ऊर्जा संकट के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला

अब राशन दुकानों से मिलेगा कुकिंग कोयला

लोकतंत्र की शान , पटना

बिहार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब जन वितरण प्रणाली (PDS) यानी राशन दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला मौजूदा ऊर्जा संकट को देखते हुए लिया गया है।

क्यों लेना पड़ा यह फैसला?: सरकार के अनुसार, वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत के कई हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। रसोई गैस (LPG) की उपलब्धता में कमी और बढ़ती कीमतों की वजह से गरीब परिवारों के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया है। इसी समस्या के समाधान के तौर पर सरकार ने कुकिंग कोयला को एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

BPL कार्ड धारकों के हित में बड़ा फैसला- नीरज कुमार: LPG गैस क्राइसिस के बीच बिहार सरकार के इस फैसले पर भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि, 'बिहार सरकार ने BPL कार्ड धारकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सभी राशन कार्ड धारी को कोयला देने का निर्णय लिया है। उसके लिए राज्य के खाद्य उपभोक्ता सरंक्षण विभाग ने खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग और जिले के सभी डीएम को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सहरसा में सोलर मेला सह लोन मेला आयोजित ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन, सब्सिडी व आसान ऋण से उपभोक्ताओं को मिला लाभ स्वच्छ, सस्ती एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में अहम पहल

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता: आम नागरिकों को सस्ती, सुलभ एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सोलर अधिष्ठापन में तेजी लाने के लिए जिला पदाधिकारी, सहरसा के निर्देश पर बुधवार को प्रेक्षागृह भवन, सहरसा परिसर में विद्युत विभाग एवं बैंकों के संयुक्त तत्वावधान में सोलर मेला सह लोन मेला का सफल आयोजन किया गया। मेले का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्रणाली के प्रति जागरूक करना एवं उन्हें योजना से जोड़ना था। इस अवसर पर विशेषज्ञों एवं तकनीकी टीम द्वारा सोलर पैनल की स्थापना, कार्यप्रणाली, रख-रखाव, लागत, अनुदान (सब्सिडी) तथा उससे होने वाले आर्थिक लाभ की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं का

मौके पर ही समाधान किया गया। इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, जिससे वे तुरंत आवेदन कर योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया शुरू कर सके। विभिन्न अधिकृत वेंडर्स एवं एजेंसियों ने भाग लेकर उपभोक्ताओं को उपयुक्त सोलर समाधान उपलब्ध कराने में सहयोग किया। विद्युत अधीक्षण अभियंता, सहरसा ई. संतोष कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिससे बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आती है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, सोलर संयंत्र स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से लगभग 7 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का ऋण भी उपलब्ध है। जिले में अब तक 75 उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 68 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो चुका है।

महा-ठगबंधन" के खिलाफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का धिक्कार मार्च, सहरसा में गूंजे विरोध के स्वर

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के पार्टी आलाकमान के आह्वान पर सहरसा जिला इकाई द्वारा महागठबंधन की कथित जनविरोधी नीतियों, महिला विरोधी सोच एवं विकास विरोधी राजनीति के खिलाफ जोरदार "धिक्कार मार्च" निकाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष आरती देवी ने की, जबकि संचालन प्रधान महासचिव सी.एम. झा बोआ द्वारा किया गया। यह धिक्कार मार्च वीर कुंवर सिंह चौक से प्रारंभ होकर शंकर चौक तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन के विरोध में जमकर नारेबाजी की और महिला सम्मान, सामाजिक न्याय एवं विकास के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने महागठबंधन पर तीखा प्रहार करते हुए इसे "महा-ठगबंधन" करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गठबंधन जनता को भ्रमित करने और समाज को पीछे धकेलने का कार्य कर रहा है। नेताओं ने कहा कि महिलाएं जो पूरे परिवार को संभालती हैं, उन्हें दबाने की मानसिकता इनकी नीतियों में झलकती है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण एवं न्यायपूर्ण परिसीमन के रास्ते में यही लोग बाधा बन रहे हैं। नेताओं ने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, जीतन

राम मांझी एवं चिराग पासवान के नेतृत्व में एनडीए का प्रत्येक कार्यकर्ता इस मानसिकता का मुंहतोड़ जवाब देगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदेश महासचिव शिवेन्द्र कुमार जीशू, चंदन बागची, प्रदेश उपाध्यक्ष रौशन पाठक, बैजनाथ कुमार विमल, चंद्रमोहन सिन्हा, अविनाश सिन्हा, गोपाल तिवारी, दिनेश कुशवाहा, मज़रुद्दीन खान बबलू, बालकृष्ण कुशवाहा, शैलेश झा, गौरव सिंह, बबीता देवी, सुमन देवी, काजल देवी, मुस्कान देवी, चांदनी देवी, बुल्कुन देवी, सब्जा खातून, जैनब खातून, गीता देवी, पूनम देवी, रीना देवी, मधुलता देवी, स्नेहा देवी सहित कई गणमान्य लोग एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन जारी रहेगा और जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका अधिकार तथा महिलाओं को उनका सम्मान नहीं मिलता, तब तक पार्टी सड़कों पर संघर्ष करती रहेगी।

रकिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एमएमडीपी किट पर कार्यशाला आयोजित, लाभार्थियों को मिला प्रशिक्षण व किट वितरण

लोकतंत्र की शान

सहरसा, मो. ज़ियाउद्दीन, जिला संवाददाता: सत्तर कटैया प्रखंड अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर, रकिया में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एमएमडीपी किट पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) रुपेश कुमार ने की। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को एमएमडीपी किट के उपयोग, उसके महत्व और स्वास्थ्य प्रबंधन में इसकी भूमिका के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान कुल 6 चयनित लाभार्थियों के बीच एमएमडीपी किट का वितरण किया गया। किट वितरण के साथ-साथ लाभार्थियों को इसके सही और प्रभावी उपयोग के बारे में विस्तृत

प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञों ने बताया कि यह किट विशेष रूप से दीर्घकालिक रोगों के प्रबंधन में सहायक है और इसके नियमित उपयोग से स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार संभव है। साथ ही, किट के उपयोग का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया, जिससे लाभार्थी इसे अपने दैनिक जीवन में आसानी से अपना सकें। इस अवसर पर पिरामल स्वास्थ्य के प्रोग्राम लीडर आलोक कुमार, प्रोग्राम ऑफिसर गोपाल कुमार झा, बी.डी.सी. माधव झा, तथा पिरामल स्वास्थ्य से जुड़े अखिलेश कुमार एवं विभूति चंद्र युगल उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने अपने विचार साझा करते हुए इस प्रकार की पहल को ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि जागरूकता और उचित प्रशिक्षण के माध्यम से ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है।

नाले में पलटी जेसीबी मशीन, निर्माण कार्य के दौरान सड़क धंसने से हादसा

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के जय प्रकाश नगर इलाके में मंगलवार देर शाम को बड़ा हादसा हो गया। जय प्रकाश नगर स्थित आशीर्वाद भवन के पास अचानक सड़क धंसने से वहां काम कर रही जेसीबी (खुदाई मशीन) असंतुलित होकर नाले में पलट गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जेसीबी चला रहा ड्राइवर भी सुरक्षित है।

निर्माण कार्य के दौरान हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के समय इलाके में सड़क निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान सड़क का एक हिस्सा अचानक कमजोर होकर बैठ गया, जिससे भारी

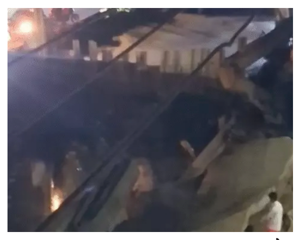

मशीन का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। स्थानीय निवासी विशाल सिंह ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में और बड़े हादसे हो सकते हैं।

आरएलएम कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च

लोकतंत्र की शान , पटना

महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद NDA का विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) आज पूरे बिहार में धिक्कार मार्च निकाल रही है। पटना में RLM कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में RLM की रैली में महिलाओं से अधिक पुरुष नजर आए। महिलाएं सिर्फ 3 दिखीं। प्रदर्शन के दौरान पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी पहुंचे। कुशवाहा की पत्नी और बहू इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुईं।

महिला आरक्षण बिल के समर्थन में प्रदर्शन

पटना के अलावा समस्तीपुर, नालंदा और औरंगाबाद में भी RLM नेताओं ने प्रदर्शन किया। लखीसराय में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं, खगड़िया में RLM कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पुतले फूंके।

महिला आरक्षण रोककर विपक्ष ने उनका हक छीना: RLM का कहना है कि इस मार्च के जरिए वे जनता तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि संसद में महिलाओं के अधिकार और प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को किस तरह रोका गया। पार्टी इसे जनजागरूकता अभियान के रूप में भी देख रही है। पार्टी नेताओं का कहना है महागठबंधन ने लोकसभा में महिला आरक्षण के खिलाफ वोट देकर महिलाओं से उनका हक छीनने का काम किया है। इससे लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का रास्ता रुक गया है।

संक्षिप्त समाचार

यूपी बोर्ड रिजल्ट कल 4 बजे होगा घोषित, योगी सरकार ने पारदर्शिता और समयबद्धता से रचा नया मानक

लोकतंत्र की शान : लखनऊ/प्रयागराज। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परिणाम गुरुवार 23 अप्रैल को अपराह्न 4:00 बजे परिषद मुख्यालय, प्रयागराज से घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परिणाम परिषद की आधिकारिक वेबसाइट और डिजिलॉकर पोर्टल पर देख सकेंगे।परीक्षाफल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट और डिजिलॉकर रिजल्ट पोर्टल पर देखा जा सकेगा, जिससे छात्रों को घर बैठे ही आसान और त्वरित तरीके से परिणाम प्राप्त हो सकेगा।

50 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षा-इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच प्रदेश के 8033 परीक्षा केंद्रों पर 15 कार्यदिवसों में शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराई गईं। हाईस्कूल में लगभग 26.02 लाख और इंटरमीडिएट में 24.91 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के व्यापक दायरे को दर्शाता है।

रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ मूल्यांकन कार्य-परीक्षाओं के सफल आयोजन के बाद 254 मूल्यांकन केंद्रों पर लगभग 2.75 करोड़ उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच मात्र 15 कार्यदिवसों में पूरा किया गया। इस बार परिणाम को त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रधानाचार्यों और वरिष्ठ प्रवक्ताओं को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

नकलविहीन और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली फोकस-योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार की सख्त निगरानी और प्रभावी व्यवस्थाओं के चलते परीक्षाएं पूरी तरह नकलविहीन और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुईं। परीक्षा से लेकर मूल्यांकन और परिणाम घोषित करने तक की प्रक्रिया में तय समयसीमा का पालन कर नया मानक स्थापित किया गया है।

पंजाब के छह जिलों में बिजली कटौती से मचा घमासान, जनता परेशान

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। पंजाब के शहरों में बुधवार से शुरू हुए बिजली कटों को लेकर राज्य की सियासत गरमा गई है। पंजाब के छह जिलों में आज से बिजली के कट शुरू हुए हैं। यह कट आगामी 26 अप्रैल तक चलेंगे। राज्य सरकार की तरफ से मंगलवार को इस संबंध में सभी समाचार पत्रों में इश्तिहारजारी करके बिजली कटों का कार्यक्रम जारी किया गया है। अधिकारिक रूप से यह कट आठ से दस घंटे तक लगेंगे। पंजाब सरकार ने पीएसपीसीएल के माध्यम से कहा है कि लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, मोहाली, बठिंडा तथा पटियाला में 26 अप्रैल तक बिजली कट लगाए जाएंगे। कट की अवधि कम से कम आठ घंटे रखी गई है। इसके लिए पावरकॉम ने बिजली डिस्ट्रिब्यूशन में सुधार और मॉडर्नाइजेशन का हवाला दिया है। पंजाब मेंलगातार गर्मी बढ़ रही है और मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए हीटवेवका यलो अलर्ट जारी किया है। 21 जिलों में तापमान 35 पार हो चुका है। बिजली कटों से परेशान लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। बीती रात अमृतसर में बिजली कट से परेशान होकर लोग देर रात को बिजली घर में घुस गए। उन्होंने बिजली घर का गेट तोड़ दिया और खुद ही बिजली सप्लाई चालू कर दी। मुलाजिमों ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी धक्कामुक्की की। बुधवार से यह कट नियमित रूप से लगने शुरू हो गए हैं। बिजली कटों से जहां जनता परेशान हो रही है वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अकाली दल प्रवक्ता एनके शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य में बिजली संकट गहरा गया है। अकाली दल की सरकार में पंजाब बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस स्टेट था लेकिन आज हालात यह हैं कि बिजली महंगे दामों पर खरीदी जा रही है। कट को लेकर बिगड़ते हालात के बीच पंजाब के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पीएसपीसीएल द्वारा घोषित नियोजित बिजली कटौती का उद्देश्य सिस्टम अपग्रेड के माध्यम से बिजली आपूर्ति में सुधार करना है। इससे होने वाली असुविधा के लिए खेद है, लेकिन ये सुधार लंबे समय में उपभोक्ताओं के लिए काफी लाभकारी साबित होंगे।

सुरक्षा गार्ड साथियों को लेकर ओटी में घुसा, नर्सिंग स्टाफ से मारपीट

लोकतंत्र की शान : जोधपुर। शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में आर्थोपैडिक ऑपरेशन थियेटर में अस्पताल का एक पूर्व सुरक्षा गार्ड घुस गया। उसने नर्सिंग स्टाफ से मारपीट, धक्काधूम की और जान की धमकीं दी। संविदा पर लगे एक अन्य नर्सिंग स्टाफ की तरफ से पूर्व सुरक्षा गार्ड सहित अन्य के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और धमकाने का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान की है, संभवत : उसे आज शाम तक पकड़ा जा सकता है। सरदारपुरा पुलिस थाने के एएसआई रमेश विश्नोई ने बताया कि चांदपोल निवासी मोन्टु पुत्र उमरचंद जो एमजीएच में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उसकी तरफ से दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 20 अप्रैल की रात करीब 9. 30 बजे वह इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी पर था। उस समय डॉक्टरों की टीम नर्सिंग स्टॉफ विष्णु गौतम एवं राहुल पंवार डॉ विकास , डॉ दुष्यत , डॉ आर्यन मरीज की सर्जरी कर रहे थे। तब सन्नी नाम का युवक अपने तीन चार साथियों संग आया और ओटी में घुस गया। उसने स्टाफ से मारपीट करने के साथ धक्काधूम की। उसने स्टाफ को जान की धमकीं भी दी। एएसआई रमेश कुमार ने बताया कि अब तक की जांच में पता लगा कि आरोपी सन्नी एमजीएच में सुरक्षा गार्ड लगा हुआ था, जोकि दस दिनों से गैर हाजिर चल रहा था। तब ठेकेदार ने उसकी जगह पर किसी अन्य को काम पर रख लिया। वह भी संविदा पर ही लगाया गया था। इस बात को लेकर सन्नी नाराज हो गया और खुननस पाल बैठा। 20 अपै्रल की रात को आया और उक्त वारदात को अंजाम दिया गया। उसकी तलाश जारी है। शाम तक संभवत : उसे पकड़ लिया जाएगा।

इनेलो छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कृष्ण कुमार कुटेल

» कांग्रेस जिला अध्यक्ष पराग गाबा ने पार्टी का पटका पहनाकर करवाया स्वागत

लोकतंत्र की शान

करनाल : बुधवार को इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कुटेल ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके साथ इनेलो के करनाल शहरी जर्नल सेक्रेटरी कुनाल गोयल ने भी कांग्रेस जॉइन की।जिला कांग्रेस कमेटी (शहरी) के अध्यक्ष पराग गाबा ने डीसीसी कार्यालय में दोनों नेताओं को पार्टी का पटका पहनाकर और मिठाई खिलाकर औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया गया।कृष्ण कुमार कुटेल ने बताया कि उन्होंने 21 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है। उनके अनुसार, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों और बिरादरियों को समान सम्मान देती उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वे लगातार जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो सभी 543 लोकसभा सीटों पर इसे लागू किया जाना चाहिए।इस अवसर पर पराग गाबा ने कहा कि कृष्ण कुमार कुटेल जैसे अनुभवी और जमीनी नेता के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके जुड़ने से पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर कार्यक्रम में ललित आहूजा, जोगिंदर वाल्मीकि, दिलशेर डाचर, बिंदर पोसवाल, तरुण चौहान, पंकज गाबा, परवीन पुनिया, एस.के. चौधरी, भारत ढिल्लो, सपना राणा, पृथ्वी बाठ, गौरव शर्मा, सतीश बिंदल, अशोक दुग्गल, विनोद शर्मा, तेजपाल कलसोरा, राकेश ढाकवाला, कृष्ण गहलोत, बलिंद्र पुनिया, सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

असंध गौशालाओं के लिए 40.87 लाख के चेक वितरित

लोकतंत्र की शान, राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

असंध: 22 अप्रैल असंध विधानसभा क्षेत्र के विधायक योगेन्द्र राणा ने आज जनसेवा और गौ-संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए क्षेत्र की विभिन्न गौशालाओं को 40 लाख 87 हजार की अनुदान राशि के चेक वितरित किए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि गौवंश की सेवा और संरक्षण हमारी सांस्कृतिक परंपरा का अहम हिस्सा है और सरकार इसके लिए पूरी तरह समर्पित है। विधायक ने हल्के की तीन प्रमुख गौशालाओं को अनुदान राशि प्रदान की।

विधायक द्वारा -श्री कृष्ण गोपाल गौशाला (गाँव उपलाना)- 30,29,100 की राशि प्रदान की गई। मीरा बाबा शहदभूरा श्री कृष्ण गौशाला (गाँव बाहरी)- 6,67,000 की राशि का चेक दिया गया। पंचतरणी गौ धाम सेवा समिति गौशाला (गाँव अरडाना)- 3,91,000 की सहायता राशि दी गई। इस अवसर पर विधायक योगेन्द्र राणा ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की नीतियों के कारण आज गौशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा रहा है।

एस डी एम,थाना प्रभारी, परियोजना अधिकारी की सक्रियता से आधा दर्जन बाल-विवाह पर लगी रोक

आजादी के 78वर्ष बाद भी चल रही बाल विवाह की कुप्रथा

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। जिले में जिला कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर एवं कुसमी एसडीएम शैलेंद्र द्विवेदी के मार्गदर्शन पर महिला बाल विकास की प्रभारी परियोजना अधिकारी मांन कुमारी पनाडिया एवं थाना प्रभारी कुसमी अरुणा द्विवेदी की सक्रियता से कुसमी की टीम ने आधा दर्जन बाल विवाह रोककर यह साबित कर दिया है कि अधिकारियों के रहते लाडली बच्चियों का बाल विवाह नहीं किया जा सकता है।

लगातार छापामार-कार्यवाही होने को लेकर बाल विवाह करने वाले लोगों पर हड़कंप मचा हुआ है।

पूरे मामले में प्रभारी परियोजना अधिकारी मांन कुमारी ने जानकारी देकर बताया कि खण्ड स्तरीय टीम गुप्त तरीके से क्षेत्र में काम कर रही है एवं सूत्रों और समाज सेवायों की के मदद से हमें समय से जानकारी प्राप्त हो जाती रही है और थाना प्रभारी कुसमी अरूणा द्विवेदी की सक्रियता एवं टीम की मदद से कुसमी ब्लाक अंतर्गत आधा दर्जन बाल विवाह होने पर रोक लगा देने मे कामयाबी हासिल हुयी है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों से अपराध निकाल, संपत्ति संबंधी अपराधों में बरामदगी प्रतिशत, बाउंड ओवर कार्यवाही, ऑपरेशन मुस्कान एवं ऑपरेशन शिकंजा के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी ली। इसके साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध धारा 185 मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा लंबित अपराधों पर विशेष ध्यान देते हुए निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपराधों का निराकरण किया जाए। जिन विवेचकों द्वारा समयावधि पूर्ण होने के बावजूद अपराध लंबित रखे गए, उन पर 500-500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि उनका प्राथमिक स्तर पर ही त्वरित, संतोषजनक एवं पूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। महिला संबंधी अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में शीघ्र विवेचना पूर्ण कर निर्धारित समय सीमा में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त गुंडा एवं निगरानी बदमाशों की नियमित चेकिंग करने तथा उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने सभी अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गंभीरता एवं तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए।

रेरा व्यवस्था को लागू करने कार्यशाला आयोजित

» रेरा से मजबूत हो रहा रियल एस्टेट सेक्टर - क्रेताओं को सुरक्षित निवेश, प्रमोटरों को विश्वसनीयता

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के तत्वावधान में मानस भवन में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में रेरा के सचिव श्री राजेश बहुगुणा ने कहा कि भू-संपदा अधिनियम प्रमोटर और क्रेता के बीच विश्वास कायम करने का प्रभावी माध्यम है, जिससे दोनों पक्षों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित होता है। उन्होंने बताया कि रेरा व्यवस्था लागू होने के बाद रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने की संस्कृति विकसित हुई है। अधिनियम के अंतर्गत परियोजनाओं का पंजीयन अनिवार्य होने से प्रमोटरों की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, वहीं क्रेताओं को भी सुरक्षित निवेश का भरोसा मिलता है। कार्यशाला के दौरान प्रस्तुतीकरण के माध्यम से रेरा के प्रावधानों, पंजीयन प्रक्रिया, अधिकारों एवं दायित्वों की विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि अधिनियम के तहत परियोजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां सार्वजनिक करना अनिवार्य है, जिससे खरीदार सही जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें। साथ ही, विलंब की स्थिति में जवाबदेही तय करने और शिकायतों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि रेरा का दायरा शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों एवं सहकारी समितियों तक विस्तारित है, जिससे व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है। रेरा पोर्टल के माध्यम से पंजीयन, नवीनीकरण और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया गया है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने भी रेरा की आवश्यकता और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर अपने विचार साझा किए तथा आमजन को इसके प्रति जागरूक करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा, उपाध्यक्ष दानबहादुर सिंह, पार्षद पूनम सोनी, गीता सिंह, विनोद मिश्रा, आनंद परियानी, बाबूलाल कुशवाहा, हल्के सोनी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चुरहट श्री विकास आनंद, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रिया पाठक, जिला पंजीयक अभिषेक सिंह सहित जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागीय अधिकारी एवं रियल एस्टेट से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए रेरा के प्रभावी क्रियान्वयन में सभी की सहभागिता पर बल दिया गया।

कलेक्टर के जन चौपाल में नहीं पहुंच सकी महिला पटवारी तो जारी हो गया निलंबन करने का फरमान

जन चौपाल में अनुपस्थित रहने पर पटवारी के निलंबन के निर्देश

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। तहसील बहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत पोड़ी में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने हल्का पटवारी समरदह अलका त्रिपाठी के निलंबन के निर्देश दिए हैं।

जन चौपाल के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए उक्त लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन चौपाल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, ताकि आमजन की समस्याओं का समय-सीमा में प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा सके। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त।अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

नजीबाबाद में अन्नपूर्णा जनक हरि मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य शोभायात्रा निकाली गई

» चतुर्वेदी परिवार के सौजन्य से हुआ आयोजन, सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ धार्मिक कार्यक्रम

लोकतंत्र की शान, खिज़्र अहमद

नजीबाबाद, बिजनौर। नगर के अन्नपूर्णा जनक हरि मंदिर में चतुर्वेदी परिवार के सौजन्य से शिव परिवार की मूर्तियों की विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत जन जागरण शोभायात्रा के साथ हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों और प्रमुख चौराहों से होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंची। शोभायात्रा का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती लीना सिंघल द्वारा किया गया। यात्रा के दौरान भक्तगण भजन-कीर्तन करते हुए भगवान शिव के जयकारे लगाते नजर आए, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। चतुर्वेदी परिवार के विनायक चतुर्वेदी, निलोहित चतुर्वेदी एवं अभिषेक चतुर्वेदी के विशेष सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा सम्पन्न कराई गई। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें व्यापारी नेता शोभित मित्तल, कपिल शर्मा, लवी अग्रवाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता आशु अग्रवाल, नामित सभासद नमन गुप्ता, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष मनीष सैनी, मंडल उपाध्यक्ष श्रीमती गायत्री निराला, पत्रकार जितेंद्र जैन, एडवोकेट संजय सैनी जाखेटिया सहित कई सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियां शामिल रहीं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। वहीं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रम में भाग लेकर धार्मिक आयोजन को सफल बनाया। पूरे आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहित किया।

सलैया पटोरी में आधुनिक साइलो केंद्र शुरू,किसानों का तिलक लगाकर हुआ स्वागत

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। जिले में गेहूं उपार्जन व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार को सलैया पटोरी में आधुनिक साइलो केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देशन में शुरू हुए इस केंद्र पर पहुंचे किसानों का सहायक आपूर्ति अधिकारी पियूष शुक्ला द्वारा तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया गया। इसी के साथ साइलो केंद्र में गेहूं उपार्जन कार्य भी प्रारंभ हो गया। कलेक्टर श्री तिवारी की अध्यक्षता में बीते दिनों आयोजित जिला उपार्जन समिति की बैठक में किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए साइलो बैग गोदामों की उपलब्ध रिक्त क्षमता के आधार पर जिले के 22 उपार्जन केन्द्रों को सलैया पटोरी साइलो केंद्र से संबद्ध किया गया है। इस फैसले से किसानों में उत्साह का माहौल है और उपार्जन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

तहसीलवार उपार्जन केन्द्र- बहोरीबंद तहसील के उपार्जन केन्द्र - बहोरीबंद, हथियागढ़, बचैया, कुआं, कूड़न, किवलारी, बाकल, मसंधा, सिंहुड़ी, बरही (बाकल), इमलिया, कूड़ा, चांदनखेड़ा, देवरी (खरगवां), पथराडी पिपरिया, सलैया कला (पटोरी) और खमतरा। रीठी तहसील के उपार्जन केन्द्र – मोहास, बड़गांव और बकलेहटा। स्लीमनाबाद तहसील के उपार्जन केन्द्र –कौडिया और जुजावल। इन सभी केन्द्रों के किसान अब जेएसडब्ल्यू इंडस्ट्रीज साइलो, सलैया पटोरी में सुविधाजनक ढंग से समर्थन मूल्य पर अपना गेहूं विक्रय कर सकेंगे।

किसानों को मिलेंगे ये लाभ- साइलो केंद्र में गेहूं खरीदी शुरू हो जाने से उपार्जन केन्द्रों पर भीड़ में कमी आयेगी।फसल का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण होगा और तौल एवं परिवहन प्रक्रिया में सुगमता तथा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होने में मदद मिलेगी। आधुनिक साइलो प्रणाली के माध्यम से यह पहल जिले में पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान-केंद्रित उपार्जन व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तानी सेना ने क्वेटा से मेडिकल छात्रा का अपहरण किया, हॉस्टल के सामने प्रदर्शन

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सेना ने बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा स्थित बोलन मेडिकल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल पर छापामार कर छात्रा खदीजा बलोच का अपहरण कर लिया। इसकी भनक मिलते ही बाकी छात्राओं ने खदीजा को उठाकर ले जाने का विरोध करते हुए हॉस्टल के सामने प्रदर्शन किया। सभी ने खदीजा की तत्काल और सुरक्षित रिहाई की मांग की। द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार खदीजा को फ्रंटियर कोर (एफसी), मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) और काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) के अधिकारियों ने हॉस्टल से हिरासत में लिया। खदीजा बलोच बीएस नर्सिंग की सातवें सेमेस्टर की छात्रा हैं और केच जिले के हिरोंक इलाके की निवासी हैं। इसी महीने कराची के नवल इलाके में रहने वाली अवारान समुदाय की सदस्य हसीना बलोच को भी अगवा किया जा चुका है। बताया गया है कि बलोचिस्तान में जबरन गुमशुदा लोगों के खिलाफ क्वेटा प्रेस क्लब के सामने वॉयस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स (वीबीएमपी) का धरना आज 6141वें दिन में प्रवेश कर गया। मस्तुंग जिले के कुर्दगाप के लादी दश्त में पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए युवाओं राजदुत समलानी, अमानुल्लाह समलानी और इरफान मोहम्मद होसनी के परिवारों ने विरोध दर्ज कराया। परिवार के सदस्यों के अनुसार तीनों युवकों को पाकिस्तानी सेना ने 16 अप्रैल को कुर्दगाप तहसील के लादी दश्त से हिरासत में लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। वीबीएमपी के अध्यक्ष नसरुल्लाह बलोच और महासचिव हौवरान बलोच के प्रयासों के बाद तीनों युवकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए।

डेमोक्रेट शीला चेरफिलस-मैककॉर्मिक का प्रतिनिधि सभा से इस्तीफा

वाशिंगटन। अमेरिका में ईरान युद्ध से मची उथल-पुथल के बीच डेमोक्रेट शीला चेरफिलस-मैककॉर्मिक ने कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा से इस्तीफा दे दिया। उनका त्यागपत्र एक जांच के बाद आया है। इसमें पाया गया कि उन्होंने 20 से अधिक नैतिक नियमों का उल्लंघन किया। इसमें चुनाव प्रचार के लिए धन जुटाने से जुड़े कानूनों को तोड़ना भी शामिल है। चेरफिलस-मैककॉर्मिक पर बड़ा आरोप है कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से अमेरिका की आपदा राहत राशि को अपने चुनाव प्रचार में खर्च किया। साथ ही इस धन से महंगी चीजें खरीदीं। इसमें 109,000 डॉलर (81,660 पाउंड) की तीन कैरेट की पीली हीरे की अंगूठी भी शामिल है। अमेरिकी ऑनलाइन न्यूज प्लेटफार्म एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, वह एक सप्ताह के भीतर इस्तीफा देने वाली कांग्रेस की तीसरी ऐसी सदस्य बन गई हैं, जिन्होंने गलत आचरण के आरोपों और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से निकालने के लिए होने वाले मतदान के पहले इस्तीफा दिया। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है और खुद को बेदाग साबित करने का वादा किया है। कांग्रेस सदस्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने कांग्रेस की नैतिक जांच को "बदले की भावना से की गई कार्रवाई" बताया। चेरफिलस-मैककॉर्मिक 2022 में कांग्रेस के लिए चुनी गई थीं। इस मुद्दे पर चेरफिलस-मैककॉर्मिक को अपने साथी हाउस डेमोक्रेट्स के भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनसे पहले इस्तीफा देने वालों में प्रतिनिधि एरिक स्वॉलवेल और टोनी गोंजोलेस शामिल हैं। चेरफिलस-मैककॉर्मिक ने बयान में कहा कि "इन राजनीतिक खेलों में पड़ने के बजाय मैंने पीछे हटने का फ़ैसला किया, ताकि मैं अपना समय फ्लोरिडा के 20वें जिले में अपने पड़ोसियों के लिए लड़ने में लगा सकूं।"

नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने हनुमानगढ़ी-श्रीराम जन्मभूमि में की पूजा-अर्चना

अयोध्या। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने बुधवार को अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और श्रीराम जन्मभूमि में विधिवत दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धा व्यक्त करते हुए भगवान राम के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने भावुक अंदाज में कहा कि "भगवान राम हमारे पाहुन हैं और मैं अपने पाहुन के घर आया हूं।" उन्होंने कहा कि अयोध्या आना उनके लिए विशेष आध्यात्मिक अनुभव है। राज्यपाल ने रामलला के दर्शन को आस्था और गौरव का प्रतीक बताते हुए कहा कि भगवान श्रीराम केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि मर्यादा, आदर्श और नैतिकता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि करीब 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण होना देशवासियों के लिए गर्व और संतोष का विषय है। उन्होंने कहा कि राम के स्वरूप में माता सीता, लक्ष्मण और भगवान हनुमान का समावेश भारतीय संस्कृति, परिवार व्यवस्था और आदर्श जीवन मूल्यों की झलक प्रस्तुत करता है। यह समग्रता भारतीय सभ्यता की विशेषता है। नंदकिशोर यादव ने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद देशभर, विशेषकर युवाओं में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चेतना का नया उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में तेजी से हो रहे विकास और बदलते सांस्कृतिक माहौल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने अंत में कहा कि अयोध्या अब केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और आस्था का वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है।

दिल्ली, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में 4 से 5 दिनों तक लू चलने का पूर्वानुमान

नई दिल्ली। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ ही कई राज्यों में भीषण गर्मी के हालात हैं। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि अगले चार से पांच दिनों में उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों में लू की स्थिति और भी तीव्र होने की आशंका है। आईएमडी ने बुधवार को बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में 24 एवं 25 अप्रैल को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 23 से 25 अप्रैल के बीच और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22 से 26 अप्रैल के बीच लू चलने की आशंका है। राजस्थान में 24 से 26 अप्रैल, मध्य प्रदेश में 23 से 26 अप्रैल के बीच, छत्तीसगढ़ में 24 से 27 अप्रैल के बीच और गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, बिहार एवं झारखंड में 22 एवं 23 अप्रैल को लू चलने की आशंका है। लू की चेतावनी के साथ ही मौसम विभाग ने 22 से 25 अप्रैल के बीच ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक और तटीय गुजरात के कुछ इलाकों में गर्म और आर्द्र परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ओडिशा के कुछ हिस्सों के साथ ही कोंकण और गोवा में रात के समय गर्म मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बारिश से हालात में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है, साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।

बेंगलुरु में बॉयफ्रेंड को कुर्सी से बांधकर जिंदा जलाया

बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने बुधवार को एक युवती को बॉयफ्रेंड की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, युवती ने 21 अप्रैल को सरप्राइज देने का झांसा देकर युवक की आंखों पर पट्टी बांधी। फिर कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से हाथ-पैर बांधे और जिंदा जला दिया। युवती ने बॉयफ्रेंड की मौत का वीडियो भी बनाया। आरोपी प्रेमा और मृतक किरण, दोनों 27 साल के थे। दोनों शहर के राजाजीनगर स्थित मोबाइल स्टोर में साथ काम करते थे और करीब दो साल से रिलेशनशिप में थे। घटना शहर के ब्यादरहल्ली इलाके में प्रेमा के घर पर दोपहर करीब 2 बजे हुई। प्रेमा के परिवार के लोग घर पर नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर उसने किरण को बुलाया और हत्या कर दी। किरण तुमकुरु जिले के चिक्कनायकनहल्ली का रहने वाला था। नॉर्थ-वेस्ट के डीसीपी नागेश डीएल के अनुसार, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी युवती ने रोमांटिक मीटिंग के बहाने युवक को बांधा। कुछ ही मिनट बाद उसपर केरोसिन या पेट्रोल डालकर आग लगा दी। खुद को छुड़ा न पाने के कारण किरण की मौके पर ही मौत हो गई। पड़ोसियों ने चीखें और धुआं देखकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

सत्ता में आने पर आर्थिक पुनरुद्धार और औद्योगिक विकास पहली प्राथमिकता होगी

एजेंसी, कोलकाता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव इस बार केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं बल्कि अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध के विरुद्ध जनमत है। उत्तर 24 परगना जिले के दमदम (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में मतदाता जब इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का बटन दबाएंगे, तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों को जिताने के लिए नहीं होगा, बल्कि अवैध घुसपैठ, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ मतदान होगा।

अमित शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रभाव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अप्रासंगिक बयान देने लगे हैं। शाह ने दावा किया कि असम में कांग्रेस को अब तक का सबसे खराब परिणाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस खाता खोल सकती है लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में वह दोहरे अंक तक नहीं पहुंचेगी।

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने अवैध घुसपैठियों को शरण देने के लिए कोलकाता को झुग्गियों का शहर बना दिया है। शाह ने कहा कि संदेशखाली समेत राज्य के कई इलाकों में महिलाएं अवैध घुसपैठियों से परेशान हैं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी चुप हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे कई घुसपैठिए आज तृणमूल कांग्रेस के नेता बन चुके हैं।

अमित शाह ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आती है, तो नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में आर्थिक पुनरुद्धार और औद्योगिक विकास होगा। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल कभी देश का औद्योगिक केंद्र था लेकिन अब उद्योग एक-एक कर बंद हो रहे हैं या अन्य राज्यों में जा रहे हैं। शाह के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में राज्य के 6,000 उद्योग बंद हुए हैं या स्थानांतरित हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा चलाए जा रहे वसूली तंत्र को जिम्मेदार ठहराया।

दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी से रेप-हत्या, घर में शव मिला

एजेंसी, नई दिल्ली

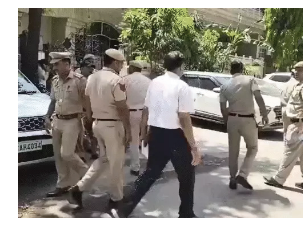

♦ पेरेंट्स जिम गए थे, नौकर पर शक, एक महीने पहले काम से निकाला था

दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में बुधवार सुबह एक सीनियर IRS अफसर के घर में उनकी 22 साल की बेटी की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, घटना सुबह करीब 6 बजे उस समय हुई जब युवती घर में अकेली थी। IRS अफसर और उनकी पत्नी रोज की तरह जिम गए हुए थे। वापस लौटे तो बेटी का शव कमरे में मिला। वह UPSC की तैयारी कर रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसके साथ पहले रेप किया गया। फिर मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से गला घोंटकर हत्या की गई।

पुलिस के मुताबिक, मामले में 19 साल का राहुल मीणा मुख्य संदिग्ध है। वह IRS अफसर के घर में करीब आठ महीने तक नौकर था। उसे करीब एक महीने पहले रोजमर्रा के खर्चों में गड़बड़ी के आरोप में नौकरी से हटा दिया गया था। सूत्रों के अनुसार, मीणा को घर की बनावट और परिवार की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी। उसे यह भी पता था कि युवती के माता-पिता कब वॉक या जिम के लिए घर से निकलते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी सुबह करीब 6 बजे घर में घुसा, युवती पर हमला किया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसने डंडे से भी हमला किया, जिससे पीड़ित के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उसने मोबाइल चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गया।

जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने 20 हजार फ्लाइट्स रद्द कीं

एजेंसी, नई दिल्ली

जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा ने मई से अक्टूबर तक 20 हजार शॉर्ट-हॉल फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला लिया है। ईरान जंग के कारण यूरोप में जेट फ्यूल की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। कंपनी के मुताबिक इससे करीब 40 हजार टन जेट फ्यूल की बचत होगी। कंपनी ने सोमवार से रोजाना करीब 120 उड़ानें घटाई हैं। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहने से तेल सप्लाई प्रभावित हुई और यूरोप में जेट फ्यूल सप्लाई की चिंता बढ़ी है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने चेतावनी दी है कि यूरोप के पास केवल 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा है।

लुफ्थांसा ने मंगलवार को कहा कि वह अपने छोटे रूट के नेटवर्क में बदलाव करके गर्मियों का फ्लाइट शेड्यूल स्थिर रखेगी। कंपनी अप्रैल के आखिर या मई की शुरुआत में पूरी योजना जारी करेगी। कंपनी ने अपने नेटवर्क में बड़े बदलाव किए हैं। फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख से घाटे वाले रूट बंद किए जा रहे हैं, जबकि ज्यूरिख, ब्रसेल्स और वियना से उड़ानें बढ़ाई जाएंगी। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की उड़ानों से बेहतर कनेक्शन मिलेगा। गर्मियों के अंत तक लंबी दूरी की उड़ानों की क्षमता थोड़ी कम की जाएगी। 6 बड़े विमान हटाए जाएंगे, 2 बोइंग 747 सर्दियों में नहीं उड़ेंगे और 4 एयरबस A340-600 विमान अक्टूबर में हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। खर्च कम करने के लिए कंपनी अपने सिटीलाइन बेड़े के 27 विमान भी बंद कर रही है। इसके पीछे महंगा ईंधन और कर्मचारियों से जुड़े विवाद मुख्य वजह बताए गए हैं।

टीजीएसआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल से तेलंगाना में बस सेवाएं ठप, लाखों यात्री प्रभावित

एजेंसी, हैदराबाद

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीजीएसआरटीसी) के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए जाने से पूरे राज्य में बस सेवाएं ठप हो गई हैं। मंगलवार आधी रात से शुरू हुई इस हड़ताल का असर बुधवार सुबह से ही साफ दिखाई देने लगा, जब राज्यभर के डिपो से बसों का संचालन पूरी तरह बंद हो गया और अधिकांश बसें सड़कों पर नहीं उतरीं। इससे यात्रा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच वार्ता विफल रहने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए वैकल्पिक इंतजाम भी नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि, सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार और समाधान के लिए एक समिति गठित की है। राजधानी हैदराबाद में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। बसों के सड़कों से गायब होने के कारण मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है और लाखों यात्री बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। स्थिति को देखते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल ने एलटीएमआरएचएल के साथ परामर्श कर मेट्रो सेवाओं के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हड़ताल के दौरान पीक और नॉन-पीक घंटों में कुल 56 ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को कुछ राहत मिल सके। इसके बावजूद कई स्टेशनों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है।

इधर, आरटीसी कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) ने चेतावनी दी है कि यदि हड़ताल तोड़ने का कोई प्रयास किया गया तो डिपो से बसों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसके जवाब में गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रमुख बस डिपो पर करीब 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती का निर्णय लिया है।

हड़ताल का सबसे अधिक असर महिलाओं, छात्रों और दैनिक कामकाजी लोगों पर पड़ा है। अकेले हैदराबाद में प्रतिदिन करीब 14.2 लाख महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाती हैं, जो अब प्रभावित हो गई हैं। बस सेवाएं बंद रहने के कारण लोगों को निजी परिवहन जैसे कैब और ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। परिवहन विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार, हड़ताल के दौरान ऑटो किराए को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो सकता है, जिससे आम जनता की परेशानियां और बढ़ सकती हैं।

इस बीच, राज्य के परिवहन मंत्री पोनम प्रभाकर ने कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की अधिकांश मांगों का समाधान किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, कर्मचारियों की 32 मांगों में से 29 पर सरकार सहमत है और उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा, जबकि शेष दो प्रमुख मांगें—आरटीसी का सरकार में विलय और यूनियन की मान्यता व चुनाव—तकनीकी जांच से जुड़ी हैं। इन पर समिति की समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के साथ चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

ब्रिटेन- 2008 के बाद जन्मे लोग तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे, जनरेशन बैन कानून दोनों सदनों में पास

एजेंसी, लंदन

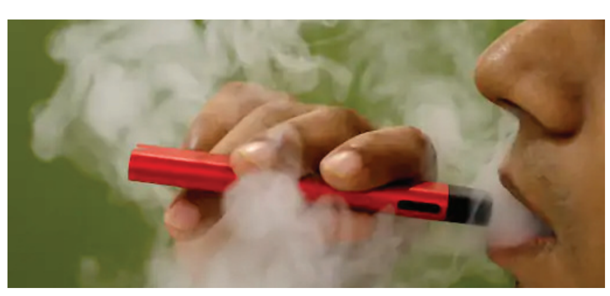

ब्रिटेन ने धूम्रपान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब वहां नई पीढ़ी के लोगों के लिए सिगरेट खरीदना हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी हो गई है। सरकार ने 'टोबैको एंड वेप्स बिल' पास कर दिया है। इसके तहत 2008 के बाद पैदा हुए लोग जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। संसद से बिल पास हो चुका है और अब सिर्फ किंग चार्ल्स III की औपचारिक मंजूरी बाकी है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। यह पूरे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में लागू होगा। सरकार ने यह बिल 2024 में पेश किया था और इसे अपनी बड़ी प्राथमिकताओं में रखा था। नए नियम के अनुसार, 1 जनवरी 2027 से यह कानून लागू होगा।

ई-सिगरेट पर भी सख्ती: वेपिंग (ई-सिगरेट) पर भी सख्ती की गई है। स्कूल, अस्पताल और बच्चों के खेलने की जगहों पर स्मोकिंग पूरी तरह बंद होगी। कई इनडोर जगहों पर वेपिंग भी नहीं कर सकेंगे। अगर कोई 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ कार में वेपिंग करता है, तो वह भी गैरकानूनी होगा। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग ने कहा है कि यह पीढ़ी लत और नुकसान से बची हुई पहली स्मोक-फ्री जनरेशन होगी। उनका कहना है कि इलाज करने से बेहतर है पहले ही बीमारी को रोक दिया जाए। सरकार का कहना है कि इससे आने वाले समय में स्मोक-फ्री जनरेशन तैयार होगी और धूम्रपान से होने वाली बीमारियां और मौतें कम होंगी। हालांकि कुछ लोग और कारोबारी इसे बहुत सख्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है।

ब्रिटेन में हर साल तंबाकू से 76 हजार मौतें: ब्रिटिश सरकार ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया है क्योंकि धूम्रपान वहां लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां हर साल 76,000 से ज्यादा लोग सिगरेट से जुड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, दिल की बीमारी और फेफड़ों की समस्या से जान गंवा देते हैं। सरकार का कहना है कि ज्यादातर लोग कम उम्र में ही सिगरेट पीना

1 जनवरी 2027 से लागू

शुरू कर देते हैं। बाद में यह आदत छोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए शुरू से ही नई पीढ़ी को इससे दूर रखना जरूरी है।

धूम्रपान की वजह से इलाज पर काफी पैसा खर्च होता है, जिससे ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा (NHS) पर दबाव बढ़ता है। अगर लोग कम धूम्रपान करेंगे, तो यह बोझ भी कम होगा। ब्रिटेन में करीब 75 प्रतिशत लोग जो सिगरेट पीते हैं, वे चाहते हैं कि उन्होंने कभी इसकी शुरुआत ही न की होती। इसके अलावा, बीमार होने की वजह से लोगों का काम भी प्रभावित होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। सरकार पहले भी चेतावनी और टैक्स जैसे उपाय कर चुकी है, लेकिन उससे पूरी तरह फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अब सख्त कानून बनाकर नई पीढ़ी को तंबाकू से दूर रखने की कोशिश की जा रही है।

तमिलनाडु के कृष्णागिरी में कार-बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत

एजेंसी, कृष्णागिरी

तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में बुधवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना होसुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हुई, जब एक कार और ओम्नी बस की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। पुलिस के मुताबिक, कार बेंगलुरु से धर्मपुरी की ओर जा रही थी, जिसमें चार लोग सवार थे। सानामावु क्षेत्र के पास पहुंचने पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद कार सामने से आ रही ओम्नी बस से टकरा गई। बस उलुंदूरपेट से यात्रियों को लेकर बेंगलुरु जा रही थी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और घायल लोग मदद के लिए पुकारते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल घटनास्थल पर पहुंचे और फंसे लोगों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया।

अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। मृतकों की पहचान धर्मपुरी जिले के सिकारा अल्ली गांव के वीरमणि, प्रताप और मारी के रूप में हुई है। वहीं घायल सतीश कुमार का उपचार चल रहा है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सभी लोग बेंगलुरु से अपने गांव मतदान करने के लिए लौट रहे थे। तभी पोननगरम की ओर जाते समय यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में 1,000 करोड़ से अधिक की जब्ती की

एजेंसी, नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान दोनों राज्यों में अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती की है। इसमें नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु और अन्य कई चीजें हैं। आयोग ने कहा कि चुनावों को हिंसा-मुक्त, भय-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त बनाने के लिए सख्त निगरानी की जा रही है।

आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 27.48 करोड़ रुपये नकद, 39 लाख लीटर शराब (मूल्य 102.45 करोड़ रुपये), 108.11 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स, 55.88 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातु और 178.83 करोड़ रुपये मूल्य के अन्य फ्रीबीज़ जब्त किए गए। कुल मिलाकर राज्य में 472.89 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है।

तमिलनाडु में 100.19 करोड़ रुपये नकद, 1.17 लाख लीटर शराब (मूल्य 3.85 करोड़ रुपये), 76.72 करोड़ रुपये मूल्य के ड्रग्स, 159.31 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातु और 259.14 करोड़ रुपये मूल्य के अन्य फ्रीबीज़ जब्त किए गए। कुल मिलाकर राज्य में 599.24 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है।

चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल में 2,728 और तमिलनाडु में 2,283 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों को तैनात किया गया है, जो शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई करती हैं। इसके अलावा दोनों राज्यों में कुल 5,363 स्थिर निगरानी टीमों को भी तैनात किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट बोला- हिंदू एकजुट रहें, संप्रदायों में बंटे नहीं

वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते, ऐसे में कमजोर हो जाएंगे

एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री और धार्मिक भेदभाव से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, 'हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए। दो संप्रदायों में बंटना नहीं चाहिए। वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते। यह सोच सही नहीं है। अगर कोई संप्रदाय अपने मंदिर को दूसरों के लिए नहीं खोलता, तो वह कमजोर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के वकील राकेश द्विवेदी की उस बात पर कही, जिसमें कहा गया था कि जहां एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा है, जबकि वे वहां जाते भी नहीं। यदि वे जाना चाहें, तो क्या इसे सामाजिक सुधार के तहत सही ठहराया जा सकता है। अगर राज्य चाहे कि अन्य संप्रदायों के लोगों को भी अनुमति दी जाए, तो वह सुधार के रूप में कानून बना सकता है।

धार्मिक आस्था के 66 मामले: सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संवैधानिक बेंच सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही है। इसके साथ धार्मिक आस्था के 66 मामले और जुड़े हैं। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में सबरीमाला में मासिक धर्म वाली महिलाओं (10-50 साल) की एंट्री पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बैन हटा दिया। फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गईं, जिसपर अब सुनवाई हो रही है। मंदिर प्रशासन महिलाओं की एंट्री का विरोध कर रहा है।

सबरीमाला मामले पर 7 अप्रैल से शुरू हुई सुनवाई: सबरीमाला मंदिर मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई है। पहले 3 दिन, 9 अप्रैल तक सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखीं। सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

ज़ेप्टो आईपीओ और भारत का रिटेल युद्धःसेबी ने 11,000 करोड़ के प्रस्तावित आईपीओ के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी?2026 के मध्य(जुलाई-सितंबर) में बाजार में आने की उम्मीद है-क्या 10 मिनट की डिलीवरी 10 लाख किराना दुकानों का भविष्य तय करेगी?

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

» हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पीएम को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बिना नियंत्रण के विस्तार करने दिया गया, तो लाखों किराना दुकानें बंद हो सकती हैं

» भारत में किराना स्टोर केवल व्यापारिक इकाई नहीं हैं; वे सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा हैं -मोहल्ले की किराना दुकान वह स्थान होती है जहां स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रवाह चलता है -एडवोकेट किशनसनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत का खुदरा बाज़ार आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सदियों से चला आ रहा पारंपरिक किराना मॉडल है,जो न केवल व्यापार का माध्यम रहा है,बल्कि सामाजिक- आर्थिक संरचना की रीढ़ भी है;वहीं दूसरी तरफ तेजी से उभरता हुआ क्विक-कॉमर्स मॉडल है,जो तकनीक,पूंजी और उपभोक्ता व्यवहार के बदलते पैटर्न के बल पर पूरे इकोसिस्टम को बदल रहा है।इस संघर्ष का ताज़ा और सबसे चर्चित उदाहरण ज़ेप्टो का प्रस्तावित 11,000 करोड़ रूपए का आईपीओ है,7 अप्रैल 2026 की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, सेबी ने ज़ेप्टो के 11,000 -12,000 करोड़रूपए (लगभग 1.3 बिलियन डॉलर) के प्रस्तावित आईपीओ के लिए सैद्धांतिक मंजूरी (इन-प्रिंसिपल अप्रूवल) दे दी है।जिसने देशभर के डिस्ट्रीब्यूटर्स और छोटे व्यापारियों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को बिना नियंत्रण के विस्तार करने दिया गया, तो लाखों किराना दुकानें बंद हो सकती हैं और भारत का पारंपरिक रिटेल सिस्टम गंभीर संकट में आ सकता है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क्रि इस पूरे विवाद का मूल प्रश्न केवल एक कंपनी या एक आईपीओ नहीं है, बल्कि यह उस बड़े बदलाव का प्रतीक है जिसमें तकनीकी नवाचार और पारंपरिक अर्थव्यवस्था आमने-सामने खड़े हैं। आल इंडिया कंस्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (ऐआईसीपीडीऍफ़) ने अपने पत्र में साफ शब्दों में कहा है कि क्विक-कॉमर्स कंपनियों का डार्क- स्टोर मॉडल स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स और छोटे खुदरा विक्रेताओं की आर्थिक नींव को कमजोर कर रहा है। डार्क स्टोर ऐसे गोदाम होते हैं जो आम ग्राहकों के लिए खुले नहीं होते, बल्कि केवल ऑनलाइन ऑर्डर की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। यह मॉडल पारंपरिक सप्लाई चेन को दरकिनार कर सीधे कंपनियों को उपभोक्ता तक पहुंचने की सुविधा देता है, जिससे बीच के डिस्ट्रीब्यूटर और छोटे दुकानदार अप्रासंगिक होते जा रहे हैं।भारत में किराना स्टोर केवल व्यापारिक इकाई नहीं हैं; वे सामाजिक ताने-बाने का हिस्सा हैं। मोहल्ले की किराना दुकान वह स्थान होती है जहां ग्राहक को उधार मिल जाता है, जहां व्यक्तिगत संबंध बनते हैं, और जहां स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रवाह चलता है। लेकिन जब ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करते हैं, भारी छूट देते हैं और ग्राहकों को ऐप-आधारित सुविधा प्रदान करते हैं, तो उपभोक्ता स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते हैं। यह बदलाव धीरे-धीरे किराना दुकानों की बिक्री को कम करता है और अंततः उनके बंद होने कासटीक कारण बन सकता है। साथियों बात अगर हम व्यापारी बंधुओ की करें तो ऐआईसीपीडीऍफ़ के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में ही लगभग 2 लाख किराना और छोटे खुदरा स्टोर बंद हो चुके हैं, और यदि यही प्रवृत्ति जारी रही तो वित्त वर्ष 2026 में लगभग 10 लाख दुकानों के बंद होने का खतरा है। यह आंकड़ा केवल व्यापारिक नुकसान नहीं दर्शाता, बल्कि यह लाखों परिवारों की आजीविका पर खतरे का संकेत है। भारत में रिटेल सेक्टर देश के सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है, जहां करोड़ों लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यदि यह क्षेत्र कमजोर होता है, तो इसका प्रभाव व्यापक आर्थिक अस्थिरता के रूप में सामने आ सकता है।दूसरी ओर, ज़ेप्टो का दृष्टिकोण पूरी तरह अलग है। कंपनी का तर्क है कि वह उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा, तेज़ सेवा और प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रदान कर रही है। 2020 में स्थापित इस कंपनी ने बेहद कम समय में असाधारण वृद्धि दर्ज की है। एफवाय 24 में लगभग 4,454 करोड़ रूपए का राजस्व एफवाय 25 में बढ़कर लगभग 9,669 रूपए करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, इस तेज़ वृद्धि के साथ घाटा भी बढ़ा है, जो यह दर्शाता है कि यह मॉडल अभी भी भारी निवेश और सब्सिडी पर निर्भर है। कंपनी ने अब तक लगभग 2.3 बिलियन डॉलर की पूंजी जुटाई है और इसका मूल्यांकन लगभग 7 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। साथियों बात अगर हम आईपीओ के माध्यम से ज़ेप्टो और अधिक पूंजी जुटाना चाहती है, इसको समझने की करें तो इससे वह अपने नेटवर्क का विस्तार कर सके, अधिक डार्क स्टोर खोल सके और अपने लॉजिस्टिक्स सिस्टम को मजबूत बना सके। लेकिन यही वह बिंदु है जहां विवाद गहराता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि आईपीओ के बाद जब कंपनी के पास और अधिक संसाधन होंगे, तो वह और आक्रामक तरीके से बाजार में उतरेगी, जिससे पारंपरिक रिटेल के लिए प्रतिस्पर्धा करना लगभग सटीक रूप से असंभव हो जाएगा। साथियों बात अगर हम यह स्थिति केवल भारत तक सीमित नहीं है, इसको समझने की करें तोवैश्विक स्तरपर भी ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स के विस्तार ने पारंपरिक रिटेल को चुनौती दी है।अमेरिका में अमेज़ॉन और वालमार्ट के बीच प्रतिस्पर्धा ने छोटे रिटेलर्स को काफी प्रभावित किया है।यूरोप में भी कई देशों ने बड़ेऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सख्त नियम लागू किए हैं ताकि स्थानीय व्यापारियों की रक्षा की जा सके।भारत में यह बहस भी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक हो सकता है क्योंकि यहां किराना दुकानों की संख्या और उनका सामाजिक महत्व बहुत अधिक है। साथियों बात अगर हम एक और महत्वपूर्ण पहलूएकाधिकार (मोनोपोली) का है इसको समझने की करें तो, जब कुछ बड़ी कंपनियां अत्यधिक पूंजी के बल पर बाजार पर कब्जा कर लेती हैं,तो प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है और अंततः उपभोक्ताओं के पास विकल्प सीमित हो जाते हैं। प्रारंभिक चरण में कंपनियां भारी छूट और ऑफर्स देकर ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, लेकिन जब बाजार पर उनकानियंत्रण मजबूत हो जाता है, तो वे कीमतों और शर्तों को अपने अनुसार तय कर सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स का डर यही है कि क्विक-कॉमर्स कंपनियां इसी दिशा में बढ़ रही हैं। साथियों बात अगर हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार की भूमिका को समझने की करें तो,इस पूरे परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक ओर सरकार डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है, ।वहीं दूसरी ओर उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि पारंपरिक व्यापार और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया द्वारा आईपीओ को सैद्धांतिक मंजूरी मिलना यह दर्शाता है कि नियामक संस्थाएं इस क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही हैं, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं?डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने पत्र में सरकार से मांग की है कि क्विक-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों की गहन जांच की जाए और डार्क-स्टोर मॉडल पर उचित नियंत्रण लगाया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो यह असंतुलन और बढ़ेगा और पारंपरिक रिटेल पूरी तरह से समाप्त हो सकता है।हालांकि, इस बहस का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता व्यवहार तेजी से बदल रहा है। आज का ग्राहक सुविधा, गति और डिजिटल अनुभव को प्राथमिकता देता है। मोबाइल ऐप के माध्यम से कुछ ही मिनटों में सामान प्राप्त करना एक नई आदत बन चुकी है। इस बदलते परिदृश्य में पारंपरिक किराना दुकानों को भी खुद को बदलना होगा। कई दुकानदार अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप ऑर्डरिंग, होम डिलीवरी और ऑनलाइन पेमेंट जैसे विकल्प सटीक रूप से अपना रहे हैं। साथियों बात अगर हम समाधान शायद किसी एक पक्ष की जीत में नहीं, बल्कि संतुलन में है, इसको समझने की करें तो, सरकार को ऐसे नियम बनाने होंगे जो नवाचार को प्रोत्साहित करें लेकिन साथ ही छोटे व्यापारियों की रक्षा भी करें। उदाहरण के लिए, डार्क स्टोर्स की संख्या और लोकेशन पर नियंत्रण, प्रिडेटरी प्राइसिंग (अत्यधिक छूट) पर रोक, और पारंपरिक रिटेलर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने के लिए प्रोत्साहन जैसी नीतियां लागू की जा सकती हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ज़ेप्टो का आईपीओ केवल एक वित्तीय घटना नहीं है; यह भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह सवाल उठाता है कि क्या भारत अपनी पारंपरिक आर्थिक संरचना को बनाए रखते हुएआधुनिक तकनीक को अपनाने में सफल होगा,या फिर यह परिवर्तन एक बड़े सामाजिक-आर्थिक संकट का कारण बनेगा।यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में यह संघर्ष और तेज़ होगा। एक ओर तकनीकी कंपनियां अपनी गति और पूंजी के बल पर बाजार पर कब्जा करने की कोशिश करेंगी, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक व्यापारी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। इस टकराव का परिणाम केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत के रोजगार, सामाजिक संरचना और आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करेगा।इसलिए, यह समय केवल चिंता का नहीं बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय लेने का है। यदि सरकार, कंपनियां और पारंपरिक व्यापारी मिलकर एक संतुलित मॉडल विकसित करते हैं, तो यह बदलाव भारत के लिए एक अवसर बन सकता है। लेकिन यदि यह संतुलन नहीं बन पाया, तो 10 मिनट की डिलीवरी की यह दौड़ लाखों लोगों के जीवन पर भारी पड़ सकती है।

-संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
9226229318

ईरान–अमेरिका सीज़फायरः आखिर क्यों नहीं बन पा रही सहमति?

सैयद इसरार हुसैन

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष केवल सैन्य टकराव नहीं, बल्कि गहरे राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक मतभेदों का परिणाम है। हाल के दिनों में सीज़फायर (युद्धविराम) की कोशिशें जरूर हुई हैं, लेकिन ईरान बार-बार इसमें पूरी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं, जिन्हें समझना जरूरी है।

1. अमेरिकी दबाव और "ब्लॉकेड पॉलिटिक्स"- ईरान का सबसे बड़ा आरोप यह है कि अमेरिका बातचीत के साथ-साथ दबाव की नीति अपना रहा है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और समुद्री रास्तों पर नौसैनिक नाकेबंदी (blockade) कर रखी है। ईरान इसे "युद्ध जैसा कदम" मानता है और कहता है कि ऐसे माहौल में बातचीत संभव नहीं। साफ शब्दों में: ईरान चाहता है कि पहले दबाव हटे, फिर बातचीत हो। अमेरिका चाहता है कि पहले समझौता हो, फिर राहत मिले। यही टकराव सबसे बड़ा अड़ंगा है।

2. भरोसे की भारी कमी ईरान और अमेरिका के रिश्ते दशकों से खराब रहे हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों के बीच अविश्वास गहरा है। हाल की बातचीत में भी ईरान ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए ईरान को डर है कि: अगर वह मान भी जाए, तो अमेरिका बाद में शर्तें बदल सकता है या फिर नए प्रतिबंध लगा सकता है

3. ईरान की अपनी शर्तें ईरान किसी भी समझौते को "बराबरी" के आधार पर करना चाहता है। उसकी मुख्य मांगें हैं: सभी प्रतिबंध हटाए जाएं भविष्य में हमले न करने की गारंटी मिले उसकी क्षेत्रीय ताकत और रणनीतिक हित (जैसे होर्मुज़ जलडमरूमध्य) को स्वीकार किया जाए जबकि अमेरिका चाहता है: ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त नियंत्रण माने क्षेत्रीय गतिविधियों पर लगाम लगाए दोनों की प्राथमिकताएँ ही अलग हैं, इसलिए सहमति मुश्किल है।

4. आंतरिक राजनीति और सत्ता संघर्ष रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के अंदर भी एकजुट नेतृत्व की कमी दिख रही है। अलग-अलग शक्ति केंद्र (सरकार, सेना, रिवोल्यूशनरी गार्ड) अलग-अलग रुख रखते हैं कुछ गुट समझौते के खिलाफ हैं इसका असर: ईरान तुरंत कोई स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहा।

5. "दबाव में झुकना" छवि के खिलाफईरान अपने आप को एक मजबूत और स्वतंत्र शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है।अगर वह अमेरिका के दबाव में समझौता करता है, तो यह घरेलू राजनीति में कमजोरी मानी जा सकती है इसलिए वह "कठोर रुख" अपनाकर अपनी छवि मजबूत रखना चाहता है

6. रणनीतिक गणित: समय किसके पक्ष में?कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों को लगता है कि समय उनके पक्ष में है।अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है ईरान क्षेत्रीय ताकत दिखाकर leverage बना रहा है इस कारण कोई भी जल्दी समझौता करने को तैयार नहीं है।

7. जमीनी स्तर पर जारी तनाव भले ही सीज़फायर घोषित हो, लेकिन: समुद्री झड़पें जारी हैं जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं यानी "सीज़फायर" पूरी तरह लागू नहीं है, जिससे भरोसा और कम होता है।

निष्कर्ष ईरान का सीज़फायर में कम रुचि दिखाना किसी एक कारण से नहीं, बल्कि कई परतों वाला मुद्दा है: अमेरिकी दबाव और नाकेबंदी आपसी अविश्वास अलग-अलग शर्तें आंतरिक राजनीति वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन जब तक इन मूल मुद्दों का समाधान नहीं होता, तब तक स्थायी शांति समझौता होना मुश्किल ही दिखता है।

सैयद इसरार हुसैन
(लेखक,/ मध्य पूर्व के विशेषज्ञ हैं)

भारतीय संसदीय इतिहास का एक काला अध्याय

राजेश कुमार सिंह, राजनीतिक संपादक

नई दिल्ली: 17 अप्रैल 2026 भारतीय संसद के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया, जब 131वां संविधान संशोधन विधेयक (महिला आरक्षण बिल) लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा। इस विफलता के मूल में केवल विधायी बाधाएं नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक बिसात और उत्तर-दक्षिण राज्यों के बीच गहराता शक्ति संतुलन का संघर्ष था।सरकार की मुख्य योजना यह थी कि मौजूदा सीटों को प्रभावित किए बिना महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके लिए लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर लगभग 850 करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, विपक्ष—विशेषकर INDIA गठबंधन—ने इसे महिला सशक्तिकरण की आड़ में एक "चुनावी छलावा" करार दिया। शशि थरूर जैसे नेताओं ने इसे "ट्रोजन हॉर्स" (Trojan Horse) की संज्ञा देते हुए आगाह किया कि इसके पीछे छिपे उद्देश्य कुछ और हैं।दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी चिंता परिसीमन (Delimitation) के आधार को लेकर थी। यदि सीटों की संख्या 2011 (या आगामी) जनगणना के आधार पर बढ़ती, तो तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को अपनी जनसंख्या नियंत्रण की सफलता की 'सजा' भुगतनी पड़ती। विपक्ष का तर्क था कि इससे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का लोकसभा में दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि दक्षिण और पूर्वोत्तर का राजनीतिक प्रभाव नगण्य हो जाएगा। इसी क्षेत्रीय असुरक्षा ने बिखरे हुए विपक्ष को एक मंच पर ला खड़ा किया। 21 घंटे की मैराथन चर्चा के दौरान विपक्ष ने एक और रणनीतिक मोर्चा खोला—ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण। तर्क दिया गया कि बिना 'कोटे के भीतर कोटे' के, यह कानून केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की महिलाओं तक सीमित रह जाएगा। सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय स्वायत्तता के इन दोहरे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति न बन पाना ही बिल के गिरने का मुख्य कारण बना।आलोचकों का मानना है कि यदि सरकार वास्तव में गंभीर होती, तो आरक्षण को परिसीमन की जटिलता से अलग रखकर 2024 या 2029 से ही लागू किया जा सकता था। बिल के विफल होने का अर्थ है कि अब भारत की महिलाओं को अपने संवैधानिक हक के लिए संभवतः 2034 तक का लंबा इंतजार करना होगा।भारतीय महिलाओं के गौरवमयी सपनों को जानबूझकर 'परिसीमन' जैसी एक ऐसी विवादास्पद प्रक्रिया की बेड़ियों में जकड़ दिया गया है, जो स्वयं अपनी निष्पक्षता के लिए सवालों के घेरे में है। भविष्य का यह परिसीमन उन राज्यों को सत्ता की अधिक शक्ति सौंपने का पुरस्कार देगा जिन्होंने आबादी पर नियंत्रण नहीं रखा, जबकि बेहतर शासन, शिक्षा और विकास के कीर्तिमान स्थापित करने वाले राज्यों को उनकी सफलता की सजा 'राजनैतिक उपेक्षा' के रूप में मिलेगी।सही मायने में क्या हम विश्व पटल पर यह संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में श्रेष्ठ योगदान देने वाले राज्यों की राजनैतिक अहमियत खत्म कर दी जाएगी? सरकार ने यह प्रस्ताव उसी अदूरदर्शी हड़बड़ी में पेश किया है, जैसी जल्दबाजी 'नोटबंदी' के समय दिखाई गई थी। इतिहास गवाह है कि नोटबंदी की उस जल्दबाजी ने देश को किन जख्मों से नवाज़ा था। आज परिसीमन के रूप में सरकार एक बार फिर वैसी ही 'राजनैतिक नोटबंदी' की तैयारी में है। यह केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि लोकतंत्र के साथ किया जाने वाला वह जुआ है, जिसकी कीमत देश के विकसित और जागरूक राज्यों को चुकानी पड़ेगी।ऐसा प्रतीत होता है मानो भारतीय महिलाओं के न्यायोचित संवैधानिक अधिकारों को 'प्रशासनिक सौदेबाजी' के एक ऐसे मकड़जाल में उलझा दिया गया है, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता राजनैतिक दांव-पेंचों की धुंध में खो गया है।महिला आरक्षण बिल की विफलता का मुख्य कारण सरकार की वह रणनीति रही, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाकर विरोध को शांत करने की कोशिश की गई। किंतु यही दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि इसने भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बुनियाद पर ही प्रहार कर दिया। विपक्ष ने इसे केवल महिला अधिकार का मुद्दा न रहने देकर एक 'राजनैतिक और प्रशासनिक जटिलता' के रूप में उजागर किया, जिससे अंततः सरकार सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने में विफल रही। भारतीय महिलाओं के सपनों को जानबूझकर एक ऐसी विवादास्पद राजनीतिक प्रक्रिया (परिसीमन) के साथ जोड़ दिया गया है, जो खुद सवालों के घेरे में है। भविष्य में होने वाला यह परिसीमन असल में उन राज्यों को अधिक ताकत देगा जिन्होंने आबादी पर लगाम नहीं लगाई, जबकि बेहतर शासन और विकास करने वाले राज्यों को उनकी सफलता की सजा 'राजनैतिक उपेक्षा' के रूप में मिलेगी।क्या हम दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि अच्छा काम करने से आपकी राजनैतिक अहमियत खत्म हो जाएगी?महिला आरक्षण बिल के गिरने के पीछे सरकार की रणनीति यह थी कि सीटों की संख्या बढ़ाकर विरोध को शांत किया जाए, लेकिन यही रणनीति उसकी विफलता का कारण बनी क्योंकि इसने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संघीय ढांचे (Federal Structure) पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने इसे महिला अधिकार के बजाय एक "राजनीतिक और प्रशासनिक जटिलता" के रूप में पेश किया, जिससे सरकार आवश्यक बहुमत जुटाने में नाकाम रही।

भारत की विदेश नीति पर गहरी चिंता, अंतरराष्ट्रीय कानून उल्लंघन पर डॉ. जया शुक्ला का तीखा बयान

जया शुक्ला

दिल्ली, दि. 22 अप्रैल, 2026: कॉंग्रेस के विचार विभाग की वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्षा डॉ.जया शुक्ला ने आज अत्यन्त क्षोभपूर्वक गहरी चिन्ता व्यक्त की। उन्हेंने कहा कि युनाइटेड नेशन्स ने भी भारत द्वारा हथियार इज़राइल भेजे जानेकी घटना को अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून का खुला उल्लंघन बताया है। उन्होंने आक्रोशपूर्वक कहा कि इसका खमियाज़ा हमारे देश को भुगतना पड़ेगा। न केवल इस एक बड़ी ग़ल्ती से हम आधे से अधिक एशिया की मित्रता खो रहे हैं, जिनमें हमारे अबतक के अच्छे मित्र भी शामिल हैं, बल्कि सुद्ध बढ़ने पर (जिसकी कि आशंका है) रूस और चीन का रुख भी चिंताजनक है। डॉ.शुक्ला ने कहा कि हमारे देश की विदेशनीति पता नहीँ किस कारण से ऐसी ही दिशाओँ मेँ चलाई जा रही है, जो देश को नुकसान पहुँचाने के लिए अंग्रेज़ी के मुहावरे "टेक्स्टबुक एग्ज़ाम्पल्स" पर सटीक बैठती है। हमारी विदेश नीति बहुत विचारपूर्वक और समझदारी से बनाई गई थी, और इसी कारण सफल भी थी। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हमारी विदेशनीति नहीँ बदली गई थी। परन्तु जबसे केन्द्र मेँ भाजपा सरकार आईहै, हमारी विदेशनीति मेँ आमूलचूल परिवर्तन होने लगे, जो देश के लिये हानिकारक हैँ। डॉ.शुक्ला ने कहा कि कई बार तो ऐसा भ्रम होने लगता है कि जैसे यह किसी पूर्वनियोजित योजना के तहत हो रहा हो।

परिसीमन बिल गिरने से देश को तो लाभ मिला

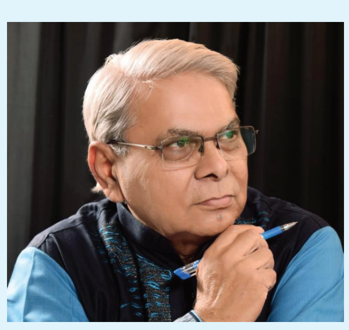

अशोक मधुप

देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को 33 फीसदी राजनीतिक आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक बिल लोकसभा में भले ही गिर गया हो किंतु भाजपा को जो लाभ मिलना था, वह मिल या। इस बिल के माध्यम से वह यह संदेश देने में कामयाब रही कि हम तो महिलाओं को संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते है, किंतु विपक्ष नही चाहता। विपक्ष भी इस बिल के गिरने को अपनी विजय मानता है। इस बिल के गिरने से भाजपा को लाभ मिले या विपक्ष को किंतु सबसे बड़ा लाभ देश को हुआ है। इस बिल के पास होने से बढ़ने वाली लोकसभा और विधान सभा सीट के सांसदों के वेतन और भत्तों का खर्च बच गया। नए सांसदों और विधायकों की पेंशन की राशि का बोझ अब देश को नही उठाना पड़ेगा। मोदी सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में वर्तमान सीटों की संख्या एकमुश्त बढ़ाकर डेढ़ गुना करने का जो प्रस्ताव इस बिल में किया था, उसका लाभ कुल मिलाकर 2250 सीटों का होता। लोकसभा में वर्तमान 545 सीटों के हिसाब से की महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से 205 सीटें बढ़तीं, जबकि सभी 28 राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में 2045 सीटों का इजाफा होता। यानी 70 करोड़ महिलाओं में से मात्र 2250 महिलाएं चुनकर विधानमंडलों में पहुंचतीं। इसमें राज्यसभा और विधानपरिषदों की सीटें शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनकी संख्या बाद में तय होगी। तर्क दिया जा सकता है कि इस आरक्षण को महिलाओं की संख्या की बजाए उनके राजनीतिक-सामाजिक सशक्तिकरण, लैंगिक समता और राजनीतिक नैतिकता की पवित्र मंशा के आईने में देखा जाना चाहिए। सही है। लेकिन अगर बिल पास हो जाता। सासंदों और विधायकों के क्षेत्र और सीट बढ़ जाती तो वढ़े सासदों , विधायकों के वेतन, भत्ते, सुविधाओं और पेंशन का बोझ तो देश पर ही पड़ता। 12 साल के कार्यकाल में यह पहला अवसर था, जब मोदी सरकार की संसद में विधायी हार हुई। संसदीय इतिहास में 1990 में पंचायत सशक्तिकरण संशोधन बिल के राज्यसभा में गिरने के बाद यह पहला बिल है, जो लोकसभा में ही ढ़ह गया। वैसे मोदी सरकार चाहती तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिल अपने दूसरे कार्यकाल में ला सकती थी, जब एनडीए के अपने 353 सांसद थे और कोई भी संशाधन बिल आसानी से पारित हो सकता था। लेकिन उसने तब ऐसा नहीं किया। भारतीय राजव्यवस्था में पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के आवंटन को लेकर एक व्यापक बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के नाम पर पुरानी पेंशन योजनाओं और सैन्य भर्ती की पारंपरिक प्रक्रियाओं में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के विस्तार के नाम पर विधायी निकायों के आकार को बढ़ाने की योजनाएं भी चर्चा के केंद्र में हैं। इन निर्णयों का भारतीय अर्थव्यवस्था और आम नागरिक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सरकार के इन कदमों के पीछे तर्क दिया जाता है कि आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग अनिवार्य है, लेकिन जब बात सांसदों और जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं की आती है, तो जनता के बीच विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पेंशन के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों में व्यापक असंतोष देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के स्थान पर नई पेंशन योजना (एनपीएस) को प्राथमिकता दी है। हालिया वर्षों में महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि तो की गई है, जैसे कि 2026 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार इसे 60 प्रतिशत तक पहुँचाया गया फिर भी यह वृद्धि कर्मचारियों की उन मांगों को शांत करने में विफल रही है। वे तो सेवानिवृत्ति के बाद एक सुनिश्चित आय की गारंटी चाहते हैं। सरकार का तर्क है कि पेंशन पर होने वाला खर्च भविष्य में विकास कार्यों के लिए उपलब्ध बजट को कम कर सकता है, इसलिए निवेश-आधारित पेंशन प्रणाली अधिक व्यावहारिक है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी इसे अपनी सामाजिक सुरक्षा में कटौती के रूप में देखते हैं, जिससे उनके भविष्य की स्थिरता पर सवालिया निशान लग जाते हैं। अर्थशास्त्री दावा करते हैं कि यदि पुरानी पेंशन दी गई तो कुछ राज्य आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगें,किंतु सासदों और विधायकों की संख्या उनके वेतन भत्तों और पेंशन से देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों की और ध्यान नही दिया जाता। यह कहीं गणना नही होती कि इससे देश पर कितना बोझ पड़ेगा। सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना इसी वित्तीय पुनर्गठन की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जाती है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद केवल 25 प्रतिशत को ही स्थायी सेवा में रखा जाता है। शेष 75 प्रतिशत युवाओं को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज देकर सेवामुक्त कर दिया जाता है, और उन्हें आजीवन पेंशन या अन्य चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जातीं। सरकार का उद्देश्य रक्षा बजट के एक बड़े हिस्से को, जो वर्तमान में वेतन और पेंशन में चला जाता है, आधुनिक हथियारों और तकनीक की खरीद में लगाना है। लेकिन इस योजना ने सुरक्षा विशेषज्ञों और युवाओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। आलोचकों का कहना है कि पेंशन के अभाव में सैनिकों का मनोबल प्रभावित हो सकता है और चार साल बाद बेरोजगार होने का डर युवाओं को इस गौरवशाली पेशे से दूर कर सकता है। एक तरफ जहां देश की सुरक्षा और प्रशासनिक सेवा में लगे लोगों के लाभों को सीमित किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर 131वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर लगभग 815 से 850 तक करने का प्रस्ताव है।इसी के साथ नए परीसीमन से विधायकों की भी 2045 सीट बढ़ने की व्यवस्था है। यह वृद्धि परिसीमन की प्रक्रिया के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। हालांकि यह कदम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से तर्कसंगत लग सकता है, पर इसके आर्थिक निहितार्थ अत्यधिक गंभीर हैं।

अभिषेक शर्मा ने तो गजब ही कर दिया

क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी सामने नहीं टिक पाया

हैदराबाद (एजेंसी)। आईपीएल 2026 का 31वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अभिषेक ने तूफानी शतक लगाते हुए क्रिस गेल के बड़े टी20 रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 68 गेंदों में 198 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 135 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 10 चौके और 10 छक्के लगाए। उनकी पारी ने इस मैच में हैदराबाद को 47 रनों से जीत दिलाई।

अभिषेक शर्मा इस इनिंग के साथ ही टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक बार 130 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा चौथी बार किया है। अभिषेक ने इस मामले में क्रिस गेल और आरोन फिंच को पीछे छोड़ा है। गेल-फिंच ने टी20 क्रिकेट में 3 बार 130 से अधिक रनों की पारी खेली है।

अभिषेक शर्मा के टी20 में 130 से ज्यादा के स्कोर

- इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 54 गेंद पर 7 चौके और 13 छक्कों से 135 रन।
- आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 55 गेंदों पर 141 रनों की पारी।
- सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के लिए बंगाल के खिलाफ 16 छक्कों की मदद से 52 गेंद पर 148 रन।
- आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 10 चौके और 10 छक्कों से 135 रन।

अभिषेक शर्मा के आगे दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए। उन्होंने आईपीएल इतिहास की पांचवीं सबसे बड़ी पारी खेली। अभिषेक ने अपनी आतिशी पारी के दौरान टी20 क्रिकेट में 350 छक्के भी पूरे किए। वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत की तरफ से संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक ने टी20 क्रिकेट में यह 9वां शतक लगाया है।

अभिषेक शर्मा की बैटिंग के मुरीद हुए दिग्गज, शतकीय पारी पर युवी से वॉर्नर तक ने ठोका सलाम

अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतक ठोका। विस्फोटक शतकीय पारी के बाद हर तरफ अभिषेक की तारीफ हो ही है। अभिषेक इस साल फॉर्म से भी जूझ रहे थे। टी20 विश्व कप के दौरान लगातार तीन पारियों में डक हुए। इस आईपीएल में भी दो बार जीरो पर आउट हो चुके हैं। लेकिन मंगलवार की रात दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के खिलाफ मनमुताबिक शॉट खेले।अभिषेक शर्मा के मेंटर युवराज सिंह ने इस पारी के बाद उन्हें शाबासी दी। युवी ने एक्स पर लिखा– बल्ले को अपना काम करने दो। हर दिन बेहतर होते जा रहे हो। बहुत बढ़िया खेले, अभिषेक सर। इसी प्रोसेस को जारी रखो।अभिषेक को कमाल का प्लेयर बताते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा– अभिषेक शर्मा, क्या बात है! बहुत बढ़िया खेले शेरा अभिषेक शर्मा। 10 छक्के, 10 चौके। सिर्फ बाउंड्रीज से ही 100 रन। कमाल का खिलाड़ी।सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टेडियम पर अभिषेक शर्मा की तारीफ की।

सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा में आदिवासी बच्चों से मिले

ऑटोग्राफ दिया, पत्नी अंजलि, बेटी सारा और बहू सानिया ने बच्चों संग बिताया समय

जगदलपुर/दंतेवाड़ा (एजेंसी)। सचिन तेंदुलकर बुधवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। वे प्राइवेट जेट से अपने परिवार के साथ जगदलपुर एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से वे सीधे दंतेवाड़ा के छिंदनार पहुंचे। जहां आदिवासी बच्चों और खेल में रुचि रखने वाले बच्चों से मुलाकात की। सचिन तेंदुलकर ने जगदलपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि दंतेवाड़ा में 50 से ज्यादा खेल मैदान का 5 हजार बच्चों को फायदा मिलेगा। वहीं, कार्यक्रम के लिए स्कूली बच्चे सुबह 9 बजे से पहुंच गए थे। यहां भीषण गर्मी में बच्चों को अलग-अलग गांव से कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। टीचर ने बताया कि एक बस में 100 से ज्यादा बच्चों को बैठाकर लाया गया। जबकि बस 50 सीटर है। जगदलपुर में सचिन ने बच्चों को बल्ले पर ऑटोग्राफ दिया। सचिन को सिहाड़ी बीज की माला पहनाई गई। बेटी सारा और बहू सानिया भी साथ दिखे।

अच्छे इंसान बनो ताकि लोग आपको याद रखें

कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हमें पता चला कि बस्तर में बच्चों के लिए ग्राउंड ही नहीं है। मेरी जिंदगी की शुरुआत मैदान से हुई थी। मैं बच्चों को देखता हूं जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, हम मैदान में जाते हैं अच्छे कोच की जरूरत होती है। हमने सोचा था कि हम अपने कोच को यहां भेजेंगे ताकि वे 100 टीचर्स को ट्रेनिंग दें। यहां डायमंड बहुत हैं, बस सही तरीके से पॉलिश करना जरूरी है। यही उम्र है खेलने कूदने की। यही उम्र है दोस्त बनाने की। मैं समझता हूं जो एक सही दोस्त होता है वो आईना दिखता है, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, इसलिए ऐसे दोस्त रखो जो ऐसे ही बनकर रहे। मेरे पिता ने एडवाइस दी कि क्रिकेट कितने साल चलेगा, मैंने कहा 10 से 15 साल, मेरे पिता ने कहा था उसके बाद क्या? आप अच्छे इंसान बनो ताकि लोग आपको याद रखें।

बच्चों के साथ समय, ग्रामीण जीवन को समझने की कोशिश

परिवार ने बच्चों को खिलौने दिए और उनके साथ समय बिताया। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान जीवनशैली, जरूरतों और समस्याओं को समझने पर खास फोकस रहा। इससे यह दौरा सिर्फ औपचारिक न रहकर जमीनी जुड़ाव का प्रयास नजर आया।

ग्रामीणों की जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी जुटाई

इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। ग्रामीणों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। तेंदुलकर परिवार ने वनांचल में ग्रामीणों की जीवन शैली और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी भी जुटाई। इस दौरान सारा तेंदुलकर ने एक आदिवासी बच्चे को गोद में लेकर प्यार और दुलार करती हुई भी नज़र आई।

जन स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर डॉक्टरों से चर्चा की

बुधवार सुबह नाश्ते के बाद तीनों गनियारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचीं। यहां स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया गया और फुलवारी केंद्र का निरीक्षण किया गया। डॉक्टरों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने बताया कि, गनियारी जन स्वास्थ्य समिति वनांचल के विभिन्न गांवों में निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रम संचालित करती है। तेंदुलकर परिवार ने समिति की तरफ से संचालित फुलवारी केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने ग्राम बम्हनी में जनस्वास्थ्य उपकेंद्र और बालवाड़ी में वनक्षेत्र के गरीब बच्चों के रहन-सहन और उपस्वास्थ्य केंद्र के संचालन को करीब से देखा। फुलवारी केंद्र में बैगा बच्चों के पोषण और शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी ली। समिति की चिकित्सकीय टीम ने उन्हें स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में बताया।

सैफ महिला चैंपियनशिप 2026

भारत ग्रुप बी में, बांग्लादेश और मालदीव से होगी टक्कर

नई दिल्ली (एजेंसी)। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के लिए ढाका में हुए ड्रॉ के बाद भारतीय महिला फुटबॉल टीम को ग्रुप बी में रखा गया है, जहां उसका सामना बांग्लादेश और मालदीव से होगा। यह टूर्नामेंट 25 मई से 6 जून 2026 तक गोवा के मडगांव में आयोजित किया जाएगा।

ग्रुप और फॉर्मेट पर एक नजर

टूर्नामेंट में कुल दो ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में नेपाल, श्रीलंका और भूटान को शामिल किया गया है, जबकि ग्रुप बी में मेजबान भारत के साथ बांग्लादेश और मालदीव हैं। हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है।

गोवा में होगा पूरा टूर्नामेंट

सभी मैच गोवा के मडगांव स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे। यह दूसरी बार है जब भारत इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2016 में सिलीगुड़ी में आयोजित संस्करण में भारत ने खिताब अपने नाम किया था।

रैंकिंग के आधार पर हुआ ड्रॉ

इस बार ड्रॉ फीफा महिला विश्व रैंकिंग के आधार पर किया गया। भारत (69वें स्थान) और नेपाल (87वें स्थान) को पॉट 1 में रखा गया था। बांग्लादेश और श्रीलंका पॉट 2 में, जबकि भूटान और मालदीव पॉट 3 में शामिल थे।

भारत का दमदार रिकॉर्ड

भारतीय महिला टीम इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, जिसने 2010, 2012, 2014, 2016 और 2019 में खिताब जीते हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन किया है और 2022 व 2024 के संस्करण अपने नाम किए हैं, जिससे इस बार मुकाबला कड़ा रहने वाला है।

आज मुम्बई इंडियंस के खिलाफ

ब्लॉकबस्टर मुकाबले में धोनी की वापसी तय

मुंबई (एजेंसी)। महेंद्र सिंह धोनी और विल जैक्स गुरुवार रात वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के बड़े मुकाबले के लिए वापसी करने को तैयार दिख रहे हैं। कल होने वाले मुकाबले धोनी की मौजूदगी संघर्ष कर रही ष्टस्य टीम के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। 44 साल के इस अनुभवी खिलाड़ी ने मंगलवार को वानखेड़े में अभ्यास किया। उन्होंने करीब आधे घंटे तक विकेटकीपिंग की और फिर 30 मिनट तक बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी का अभ्यास किया।

प्री-सीजन शिविर के दौरान पिंडली में खिंचाव से उबर रहे धोनी में किसी भी तरह की परेशानी के कोई लक्षण नहीं दिखे और वह मैच के लिए पूरी तरह तैयार नजर आए। सीएसके इस समय अंक तालिका में आठवें स्थान पर है, उसने 6 मैचों में से केवल दो मैच जीते हैं, ऐसे में धोनी की वापसी टीम के बल्लेबाजी क्रम को बहुत जरूरी स्थिरता और अनुभव दे सकती है।

वहीं मुम्बई इंडियंस की बात जाए जैक्स के लंबे समय से इंतजार हो रहे आगमन से टीम में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर ने 2026 टी-20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था और चार बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब जीता था। पहले छह मैच न खेल पाने के बाद वह अब टीम से जुड़ गए हैं। उन्होंने सोमवार शाम को वानखेड़े में ट्रेनिंग की और मंगलवार को रात की रोशनी में होने वाले सेशन के लिए भी लौटे, जहाँ उन्होंने बल्ले और गेंद, दोनों के साथ काफी समय बिताया।

जैक्स के टीम में शामिल होने से मुंबई का संतुलन मजबूत हो गया है; वह मध्यक्रम में ताकत देने के साथ-साथ ऑफ-स्पिन गेंदबाजी का एक उपयोगी विकल्प भी देते हैं। उनकी मौजूदगी टीम मैनेजमेंट को अपने विदेशी खिलाड़ियों के संयोजन में बदलाव करने पर मजबूर कर सकती है, जिसके चलते अल्लाह गजनफर या मिचेल सैंटनर में से किसी एक को टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है। निचले क्रम में अपनी जबर्दस्त छोटी पारियों के लिए मशहूर जैक्स, एक भरोसेमंद'फिनिशर'के तौर पर टीम की गहराई को भी बढ़ाते हैं।

वहीं दूसरी ओर, सीएसके को भी एक अच्छी खबर मिली है, ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन, नाथन एलिस की जगह टीम में शामिल हो गए हैं। जॉनसन ने मंगलवार को टीम के साथ अभ्यास की और उम्मीद है कि वह'प्लेइंग इलेवन'में जगह बनाएंगे; संभवतः वह चोटिल खलील अहमद की जगह लेंगे।

व्यापार

विश्व पृथ्वी दिवस पर वेदांता की बड़ी घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी। हर साल 22 अप्रैल के दिन दुनिया भर में यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता पैदा करना और ग्लोबल सस्टेनिबिलिटी को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर वेदांता लिमिटेड (ने घोषणा की है कि उसने पिछले साल रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग 50 फीसदी से भी अधिक बढ़ाया है। मेटल, ऑयल एंड गैस, क्रिटिकल मिनरल्स, पावर और टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने घोषणा की कि वित्त वर्ष 2026 में उसके रिन्यूएबल एनर्जी उपयोग में पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होकर 3.97 बिलियन यूनिट हो गई है। इस दौरान कंपनी ने 30 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचाव किया। कंपनी का कहना है कि अब स्ट्रेटेजिक मेटल्स और क्रिटिकल मिनरल्स का पोर्टफोलियो एडवांस मैन्यूफैक्चरिंग, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन और क्लीन टेक को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा हे। दुनिया भर की प्रतिष्ठित कंपनियां इस समय नेट जीरो की तरफ बढ़ रही हैं। वेदांता का कहना है कि वह नेट जीरो जर्नी की तरफ मजबूत कदम उठा रही है। उसने मेटल्स इंटेंसिटी में 15 प्रतिशत की कमी की है। यह वित्त वर्ष 2020–21 के बेसलाइन से घटकर वित्त वर्ष 2025–26 में 5.44 हो गई है। यह परिचालन दक्षता को दर्शाता है। वेदांता ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में 365 किलो टन बायोमास का भी उपयोग किया है, जिससे अनुमानित 5 से 6 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। साथ ही, कंपनी ने अपने विभिन्न कारोबार में जल संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, केर्न ऑयल एंड गैस और इसके आयरन ओर बिजनेस ने नेट वॉटर पॉजिटिव स्थिति हासिल की है।

कार्ड बदलने पर नहीं रुकेगा ऑटोमैटिक पेमेंट

15,000 तक नहीं पड़ेगी ओटीपी-पासवर्ड की जरूरत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को डिजिटल पेमेंट को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अगर किसी ग्राहक का कार्ड दोबारा जारी होता है, तो उसके पुराने कार्ड पर चल रहे ई–मैंडेट (ऑटोमैटिक पेमेंट सेटिंग्स) को नए कार्ड पर अपने आप ट्रांसफर किया जा सकेगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि जब भी किसी ऑटोमैटिक पेमेंट का नोटिफिकेशन ग्राहक के पास जाए, तो उसमें शिकायत दर्ज करने के तरीके की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। आरबीआई ने बताया कि ई–मैंडेट से जुड़े नियमों में ये बदलाव इस क्षेत्र से जुड़े लोगों और कंपनियों से मिले सुझावों के आधार पर किए गए हैं। नए नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि बार–बार होने वाले पेमेंट (जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन या बिजली बिल) के लिए ई–मैंडेट की सुविधा देने के बदले ग्राहकों से फीस या चार्ज नहीं लिया जाएगा। आरबीआई के मुताबिक, बैंकों को शिकायतों के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। केंद्रीय बैंक ने बताया कि हर महीने होने वाले 15,000 रुपये तक के ऑटोमैटिक पेमेंट के लिए अब अलग से ओटीपी या पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। अगर पेमेंट 15,000 रुपये से ज्यादा का है, तो उसके लिए ओटीपी जैसा वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वहीं, आरबीआई ने कुछ खास पेमेंट्स के लिए इस लिमिट को और भी बढ़ाया है। इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड की किश्तें और क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट के लिए 1 लाख रुपये तक के ट्रांजैक्शन बिना ओटीपी के किए जा सकेंगे।

नौकरी में एक जगह पर 2 साल भी नहीं टिक रहे युवा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में ग्लोबल कंपनियों के ऑफिसों (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर) में एक अजीब स्थिति देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां नई भर्तियों में तेजी आई है, वहीं दूसरी तरफ (आज के दौर के युवा) कर्मचारियों के जल्दी-जल्दी नौकरी छोड़ने से कंपनियां पुराने पदों को ही दोबारा भरने में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारियों के एक कंपनी में टिकने का समय 24 महीने यानी 2 साल से भी कम हो गया है। स्थिति यह है कि कंपनियों में होने वाली कुल भर्तियों में से 40 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ रिप्लेसमेंट का है। इसका मतलब है कि हर 5 में से 2 भर्तियां नई नहीं हैं, बल्कि वे उन पदों को भरने के लिए की जा रही हैं जिन्हें कर्मचारी छोड़कर चले गए हैं। खासकर टेक सेक्टर में युवा प्रोफेशनल्स बेहतर सैलरी, प्रमोशन की तेज रफ्तार जैसी आधुनिक तकनीक पर काम करने के लालच में फटाफट नौकरियां बदल रहे हैं। इस वजह से कंपनियों के लिए भर्ती करना, ट्रेनिंग देना और फिर से नई भर्ती करने का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र शुरू हो गया है।

ईरान युद्ध का असर! तेल-गैस और कच्चे माल की कीमत बढ़ी

नई दिल्ली, एजेंसी। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। एजेंसी ने पहले इसके 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था लेकिन अब इसे कम करके 6 प्रतिशत कर दिया है। इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को बताया है, जिसके चलते एनर्जी (तेल-गैस) और कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं। आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है। मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में मूडीज ने कहा कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों की वजह से भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। ईंधन और खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी पर ज्यादा खर्च होने के कारण सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ेगा, जिससे जीडीपी की रफ्तार धीमी हो सकती है। हालांकि, भारत का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और सर्विसेज एक्सपोर्ट अर्थव्यवस्था को सहारा देंगे।

मूडीज का अनुमानः एजेंसी ने इसे 6.8 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया है, इसकी मुख्य वजह पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध को बताया है, इसके चलते तेल-गैस और कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है, ईंधन-खाद पर सब्सिडी बढ़ने से सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ेगा।

इससे इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी की रफ्तार धीमी हो सकती है इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भारत की अर्थव्यवस्था के इस वर्ष 6.4 प्रतिशत और 2027 में 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया-प्रशांत (ईएससीएपी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाएं 2025 में 5.4 प्रतिशत की दर से बढ़ीं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)